

दिल्ली में जल्द लागू कर सकते हैं ग्रुप - 3, और इसके लागू होते ही दिल्ली में पंजीकृत यूरो 3 पेट्रोल और यूरो 4 डीजल वाहनों पर रोक की होगी घोषणा

संजय बाटला

नई दिल्ली। दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। हवा की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हो रहा है। एक्यूआई 400 पर होने पर ग्रुप के तीसरे चरण की पाबंदियां लागू की जाएंगी।

जाने ग्रुप-3 के तहत लगने वाली पाबंदियों और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाए जाने वाले कदम

दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग की माने तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जहरीली हवा अभी बनी रहेगी। दीवाली के आसपास स्थिति और भयावह हो सकती है। दीवाली से पहले एक्यूआई 400 पर हो सकता है। यानी ग्रुप के तीसरे चरण की पाबंदियां लागू कर दी जाएंगी।

दिल्ली के ज्यादातर इलाकों का एक्यूआई "बहुत खराब" और तीन इलाकों का "गंभीर" श्रेणी में चल रहा है। दिल्ली के आसमान पर सुबह के समय स्मॉग की चादर भी छा रही है, जिसके कारण दृश्यता का स्तर प्रभावित हो रहा है। दिल्ली के वायु प्रदूषण में करीब 14 प्रतिशत की हिस्सेदारी वाहनों के धुंए की आंकी जा रही है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन अर्ली वार्निंग सिस्टम का पूर्वानुमान है कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता "बहुत खराब" श्रेणी में ही रहेगी

और जल्द ही इसके "गंभीर" श्रेणी में चले जाने का अनुमान है। दीवाली से पहले एक्यूआई 400 पर हो जाएगा और पटाखे जलने की सूरत में दिल्ली का इस बार भी गैस चैंबर बनना तय ही है।

ग्रुप के तीसरे चरण में लगने वाली पाबंदियां

- निर्माण और तोड़फोड़ के काम में बोरिंग और ड्रिलिंग,
- पाइलिंग वर्क,
- ओपन ट्रेच सिस्टम से होने वाले सीवर लाइन, ड्रेनेज
- इलेक्ट्रिक केबल के काम,
- ईट भट्टों आदि के काम,
- आरएमसी बैंचिंग प्लांट,
- बड़े वेल्डिंग वर्क और
- गैस कटिंग काम नहीं हो सकेगा।
- कच्ची सड़कों पर गाड़ियों नहीं चलेगी।
- मलबे का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा।
- एनसीआर में सभी स्टोन क्रशर जोन बंद रहेंगे।
- एनसीआर में खनन और इससे जुड़ी गतिविधियां बंद रहेंगी।
- बीएस-तीन पेट्रोल (BS-3 Petrol) और बीएस-चार डीजल (BS-4 Diesel) की गाड़ियों पर दिल्ली के अलावा गुरुग्राम,



फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में रोक रहेगी।

- अंतरराज्यीय बसों में सिर्फ इलेक्ट्रिक, सीएनजी, बीएस- छह डीजल की बसें और टैपो ट्रेलर चलेंगे।
- राज्य सरकार को छूट होगी की वह चाहें तो पांचवीं क्लास तक के बच्चों की फिजिकल क्लासेस रोक सकती है या उन्हें ऑनलाइन मोड पर क्लासेस दी जा सकती हैं।
- बीएस-तीन के हल्के मालवाहक गाड़ियों पर भी रोक रहेगी।

गाड़ियों पर भी रोक रहेगी।

फिन पर रहेगी छूट

- बीएस-तीन के हल्के मालवाहक गाड़ियों पर रोक रहेगी पर जरूरी सामान लेकर आ रहे वाहनों को छूट दी जाएगी
- चारदीवारी के अंदर छोटे स्तर पर पेंटिंग, पॉलिशिंग, वार्निश आदि के काम के साथ सीमेंट, प्लस्टर, कोटिंग के छोटे मोटे काम, टाइल्स लगाना, काटना, स्टोन काटना चारदीवारी में हो सकेगा।

वॉटर प्रूफिंग पर रोक लेकिन केमिकल वॉटर प्रूफिंग की जा सकेगी।

- रेलवे सर्विस और स्टेशन के प्रोजेक्ट,
- मेट्रो रेल सेवा और स्टेशन,
- एयरपोर्ट और आईएसबीटी,
- राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा से जुड़ी गतिविधि,
- अस्पताल और स्वास्थ्य सुविधाएं,
- विकास परियोजनाएं जैसे हाइवे, रोड, फ्लाईओवर, ओवर ब्रिज, पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रिब्यूशन, पाइपलाइन, टेली कम्युनिकेशन

सर्विस के काम को करने की छूट रहेगी।

सिटिजन चार्टर

- कम दूरी जाने के लिए पैदल या साइकिल का इस्तेमाल करें।
- स्वच्छ तरीके से आवागमन करें।
- काम पर जाने के लिए अपनी राइड शेयर करें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें।
- गर्माहट के लिए कोयले या लकड़ी का इस्तेमाल न कर इलेक्ट्रिक हीटर का प्रयोग करें।

नोएडा एयरपोर्ट पर कब से उड़ने लगेंगे हवाई जहाज, तारीख आई सामने; डीएम ने की बैठक

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ट्रायल रन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में एयरक्राफ्ट के टेकऑफ और लैंडिंग के रास्ते की बाधाओं की समीक्षा की गई। 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक बिना यात्री के ट्रायल होगा। जनवरी से टिकटों की बिक्री शुरू हो जाएगी। 30 नवंबर को क्रू मेंबर के साथ विमान को एयरपोर्ट के रनवे पर उतारा जाएगा।



ग्रेंटर नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्रस्तावित ट्रायल पहले की तैयारी शुरू हो गई है। एयरपोर्ट साइट पर सोमवार को जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में एयरक्राफ्ट के टेकऑफ व लैंडिंग के रास्ते की बाधाओं की समीक्षा की गई। इसमें विकासकर्ता कंपनी के अलावा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. के अधिकारी शामिल हुए।

एयरफ्रीड एन्वायरमेंट मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में एयरपोर्ट (Jewar Airport) पर उतरने व उड़ान भरने वाले विमानों के रास्ते में आने वाली बाधाओं को समय से चिह्नित कर उन्हें दूर करने के निर्देश दिए गए। विमानों के मार्ग में उन स्थानों की चिह्नित करने के निर्देश दिए गए, जहां पक्षियों के होने की अधिक आशंका रहती है। इसकी वजह से हादसे की आशंका हो सकती है।

एक महीने तक होगा ट्रायल

जात कि एयरपोर्ट पर 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक बिना यात्री के ट्रायल होगा। 30 नवंबर को क्रू मेंबर के साथ विमान को एयरपोर्ट के रनवे पर उतारा जाएगा। इसके बाद ही एयरपोर्ट को एयरोड्रोम लाइसेंस के लिए महानिदेशक नागर विमानन के यहां आवेदन किया जाएगा।

जनवरी से मिलेंगे टिकट
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह का कहना है कि 20 मार्च को लाइसेंस मिलने की संभावना है। जनवरी फरवरी से टिकट की बिक्री शुरू हो जाएगी।

एयरपोर्ट के पास बनेगा एक्सपोर्ट हब
देश के कृषि उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक्सपोर्ट हब विकसित करने का रणनीति है। करीब छह साल पहले यमुना प्राधिकरण

ने भी फ्रांस के रॉसिंग अंतरराष्ट्रीय मंडी की तर्ज पर मंडी विकसित करने की योजना तैयार की थी, लेकिन बाद में इस परियोजना को आगे नहीं बढ़ाया गया था।

वैश्विक बाजार तक पहुंचेंगे फसल उत्पाद
एक्सपोर्ट हब विकसित होने से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रभावित क्षेत्र से जुड़े 26 जिलों के किसानों को फायदा होगा। एयरपोर्ट कार्गो के जरिये उनके फसल उत्पाद वैश्विक बाजार तक पहुंचेंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के लिए 26 जिलों में अध्ययन कर व्यावसायिक रिपोर्ट तैयार की गई थी।

इसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड के जिले शामिल हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा और उत्तराखंड सब्जी, फल, दुग्ध व अन्य कृषि उत्पादों के उत्पादन में अग्रणी है।

दिवाली को लेकर डीएमआरसी की खास तैयारी, दो दिन यात्रियों को मिलेगा भरपूर लाभ

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो दो दिन अतिरिक्त फेरे लगाएगी। डीएमआरसी का कहना है कि मंगलवार और बुधवार को सभी लाइनों पर 60 अतिरिक्त फेरे लगाए जाएंगे। त्योहारों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने लोगों से यातायात और प्रदूषण से बचने के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की अपील की है। डीएमआरसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा कि दिल्ली मेट्रो सभी यात्रियों के लिए सुगम और अधिक सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार और बुधवार को 60 अतिरिक्त फेरे लगा रही है। सामान्य दिनों में मेट्रो के प्रतिदिन लगभग 4,000 फेरे होते हैं।

दिवाली को लेकर हाईअलर्ट पर दिल्ली के सभी अस्पताल
दिवाली को देखते हुए दिल्ली के सभी अस्पताल हाई अलर्ट पर रखे गए हैं। अस्पतालों की आपातकालीन सेवाओं में लगे डॉक्टर व अन्य स्वास्थ्यकर्मियों को अस्पताल में मौजूद रहने को कहा गया है।

डॉक्टरों का कहना है कि दिवाली के दौरान आग से जलने, दुर्घटना सहित दूसरे मामलों के काफी मरीज आते हैं। ऐसे मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त सुविधाओं के लिए इमरजेंसी सुविधाओं को मजबूत किया गया



दिल्ली मेट्रो का नया अपडेट

है। एम्स, सफदरजंग, डॉ. राम मनोहर लोहिया, लोकनायक, जीटीबी, डीडीयू सहित दिल्ली के सभी अस्पतालों में डॉक्टर तैनात रहेंगे। वहीं कुछ डॉक्टरों ने बताया कि दिवाली को देखते हुए उनकी छुट्टी तक रद्द कर दी गई है।

दिवाली की रात अग्निशमन विभाग के 3200 कर्मियों की रहेगी तैनाती

दिवाली पर दिल्ली अग्निशमन विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी अलर्ट पर रहेंगे। दिल्ली पुलिस ने पहले से ही सुरक्षा बढ़ा दी है। दिल्ली अग्निशमन विभाग ने एहतियात के तौर पर भीड़भाड़ वाले इलाकों के पास दमकल गाड़ियों को तैनात कर दिया है। वहीं 31 अक्टूबर और एक नवंबर को विभाग ने अपने सभी

अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं।

दिल्ली अग्निशमन विभाग के निदेशक अतुल गर्ग का कहना है कि दिवाली की रात शहर भर में अग्निशमन विभाग के 3200 कर्मचारी तैनात रहेंगे। अधिकारियों का कहना है कि राजधानी में सरकार की ओर से पटाखों पर बैन लगाया है ऐसे में उम्मीद है कि आग लगने की घटनाएं ज्यादा नहीं होंगी। हालांकि लाइटों के चलते शॉर्ट सर्किट से आग लगने की घटनाएं हो सकती हैं।

अधिकारियों ने बताया कि दिवाली पर अग्निशमन कर्मियों को हर समय तैयार रहने की जरूरत होती है। 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को शाम 5 बजे से आधी रात तक 23 व्यस्त स्थानों पर एक-एक दमकल की

गाड़ियां तैनात होंगी। बीते दिवाली पर मिली काल का विश्लेषण कर ऐसे स्थानों का चयन किया गया है जहां पर आग लगने की अधिक आशंका है। 1 नवंबर को नौ अलग-अलग स्थानों पर मोटरसाइकिल (बैक-पैक) यूनित तैनात की जाएंगी और सात अलग-अलग स्थानों पर क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी) तैनात रहेंगी।

इन स्थानों पर रहेगी विशेष नजर...

तिलक नगर, लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट, लाहौरी गेट, नांगलोई, साउथ एक्सटेंशन, सोनिया विहार, महरौली, अलीपुर थाना, रानी बाग मार्केट, गांधी नगर मार्केट, महिपालपुर चौक, मुंडका मेट्रो स्टेशन, आजाद मार्केट चौक, जयपुर गौल्डन अस्पताल और राधा स्वामी सल्लंग, कर्नाट प्लेस, सफदरजंग, शंकर रोड, लक्ष्मी नगर, जनकपुरी और सीबीडी शाहदरा जैसे स्थानों पर अग्निशमन उपकरणों से लैस वाहन तैनात होंगे।

शॉर्ट सर्किट होने पर होती है अधिकतर आग की घटनाएं...

अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दिवाली की रात पटाखों से आग लगने की घटनाएं कम होती हैं। जबकि घरों में लाइटों के चलते शॉर्ट सर्किट से लगी आग को लेकर अधिक काल होती है। दिवाली की रात 2023 में 208, 2022 में 201, 2021 में 152, 2020 में 205, 2019 में 245 आग लगने की काल मिली थी।

नोएडा में इन मार्गों पर नो पार्किंग, वाहन खड़ा किया तो उठा ले जाएगी पुलिस; जान लें ट्रैफिक एडवायजरी

नोएडा में धनतेरस दीवाली और भैयादूज के लिए ट्रैफिक एडवायजरी जारी कर दी गई है। अट्टा मार्केट इंदिरा मार्केट सेक्टर-18 जीआईपी मॉल गार्डन गलेरिया मॉल डीएलएफ मॉल ब्रह्मपुत्र मार्केट लॉजिक्स मॉल सिटी सेंटर होशियारपुर शॉपिंग मॉल सेक्टर-37 बॉटिनकल गार्डन किसान चौक सूरजपुर जगतफार्म परी चौक कस्बा कासना और दादरी आदि में वाहनों के दबाव को लेकर यातायात व्यवस्था और डायवर्जन की जानकारी दी गई है।



मागों को नो-पार्किंग जोन बनाया गया है। नो-पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने पर वाहनों को क्रैन द्वारा टोह कर कारवाई की जाएगी।

अट्टापीर चौक से कार मार्केट सेक्टर-28 एवं अट्टा चौक से अट्टापीर तक ई-रिक्शा, ऑटो, टैपो का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा जो पूर्व से ही लागू है।

आमजनन व वाहन चालक अट्टा मार्केट, इंदिरा मार्केट, ब्रह्मपुत्र मार्केट, डीएलएफ मॉल (DLF Mall), सेंटर

स्टेज मॉल, गुरुद्वारा, जीआईपी मॉल, गार्डन गलेरिया मॉल आदि में आने हेतु अपने वाहनों को डीएलएफ मॉल, सेंटर स्टेज मॉल, गुरुद्वारा, जीआईपी मॉल, गार्डन गलेरिया मॉल के अंदर स्थित पार्किंग में या इसके अतिरिक्त सेक्टर-18 स्थित मल्टीलेवल पार्किंग में पार्क कर शॉपिंग इत्यादि कार्य कर सकेंगे।

लॉजिक्स मॉल सिटी करनयेर के आसपास मुख्य मार्गों को नो पार्किंग जोन बनाया गया है। नो-पार्किंग जोन में

वाहन खड़ा पाये जाने पर ई-चालान की कार्रवाई की जायेगी और वाहन को मार्ग से नहीं हटाए जाने पर क्रैन द्वारा टोह कर विधिक कार्यवाही की जाएगी।

अट्टा मार्केट सेक्टर-27, इंदिरा मार्केट सेक्टर-27, सेक्टर-18, जीआईपी मॉल, गार्डन गलेरिया मॉल, डीएलएफ मॉल, ब्रह्मपुत्र मार्केट सेक्टर-28, लॉजिक्स मॉल सिटी सेंटर, शॉपिंग मॉल, होशियारपुर, किसान चौक, सूरजपुर, जगतफार्म, परी चौक, कस्बा कासना एवं दादरी पर आवश्यकतानुसार यातायात का डायवर्जन किया जाएगा।

असुविधा होने पर करें कॉल
डीसीपी ने बताया कि यातायात संबंधी असुविधा उत्पन्न होने पर यातायात हेल्पलाइन नंबर 9971009001 पर संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करने की अपील की।

ग्रेंटर नोएडा में लिगेसी प्रोजेक्ट पॉलिसी का फ्लैट खरीदारों को मिला फायदा
अमिताभ कांत समिति के सिफारिशों के आधार पर रियल एस्टेट के लिगेसी परियोजनाओं की अडचनों को हल करने के लिए लाई गई नीति व पैकेज का अब तक 73 बिलियन परियोजनाओं को लाभ मिला है। उनको पूरा कर खरीदारों को उनका आशियाना देने का रास्ता साफ हुआ है। इन 73 परियोजनाओं में शामिल लगभग 62912 फ्लैटों में से अब तक 30477 फ्लैटों की रजिस्ट्री हो चुकी है।

टॉल्वा ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA
TOLWA
TOLWA
website :- www.tolwa.in
Email :- tolwadelhi@gmail.com
bathlajanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सेवशन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम-डीएल-0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए-4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मैन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ बड़ौदा दिल्ली 110042

धनतेरस से दीपावली का शंखानंद-भाई दूज तक पंचदिवसीय महापर्व शुरू



दीप जले दीपावली आई - 5 दिवसीय महापर्व - धनतेरस से दीपावली पर्व का आगाज दुनियाँ के हर देश में बसे भारतवंशी धनतेरस से भाई दूज तक फिर छठ महात्योहार में खुशियों से सरोबार होंगे - एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र

गोंदिया - वैश्विक स्तर पर अगर हम गहराई से देखें तो भारत में करीब करीब हर दिन किसी न किसी पर्व को मनाने का होता है। कभी सामाजिक जातीय धार्मिक, राष्ट्रीय तो कभी चुनावी महापर्व जैसे 20 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र और झारखंड का चुनावी महापर्व तथा 23 नवंबर 2024 को परिणाम आने का महापर्व मनाने का दिन है, इन त्योहारों का एक महत्वपूर्ण भाव अनेकता में एकता है, इसके कारण ही भारत एक विशालकाय जनसंख्या वाला देश विभिन्न धर्मों जातियों उपजातियों के बीच सर्वधर्म सद्भाव के प्रेम से संजोया हुआ एक खूबसूरत गुलदस्ता है, इसीलिए ही हर धर्म समाज का पर्व हर दिन आनास्वाभाविक है। परंतु उन कुछ पर्वों में से धनतेरस से दीपावली और फिर छठ महापर्व एक ऐसा खूबसूरत त्योहार पर्व है जिसे भारत में ही नहीं पूरी दुनियाँ में बसे भारतवंशियों द्वारा बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 29 अक्टूबर 2024 से हो गई है जो 5 दिन तक बड़ी सौहार्दपूर्ण के साथ और खुशियों के साथ मनाया जा रहा है, फिर अब दीपावली के छठम दिन से छठ पर्व मनाया जाएगा, जो धार्मिक आस्था का खूबसूरत प्रतीक है।

क्रि.दि.प. जले दीपावली आई, धनतेरस से दीपावली का आगाज कर दिया है और पांच दिवसीय दीपावली पर्व का धनतेरस के भावपूर्ण स्वागत से शुरू हो गया है, इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे दुनियाँ के हर देश में बसे भारतवंशी धनतेरस से भाई दूज तक फिर छठ के महात्योहार में खुशियों से सरोबार होकर पूर्ण तुल्य होंगे।

साथियों बात अगर हम दीपावली महापर्व की शुरुआत धनतेरस मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 से शुरू होने की करें तो, दीपावली का शुभारंभ धनतेरस के दिन से ही हो जाता है और भाई दूज

तक यह 5 दिवसीय उत्सव मनाया जाता है। सबसे पहले धनतेरस, फिर नरक चतुर्दशी, उसके बाद बड़ी दिवाली, फिर गोवर्द्धन पूजा और सबसे आखिर में भाई दूज पर इस पर्व की समाप्ति होती है। धनतेरस इस बार आज 29 अक्टूबर 2024 को मनाई जा रही है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं में यह बताया गया है कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन से भगवान धनवंतरी प्रकट हुए थे और उनके हाथ में अमृत से भरा कलश था। उन्हें विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है।

धनतेरस को उनके प्राकट्योत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन धन के देवता कुबेर जी और धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है और सोने-चांदी के अलावा बर्तनों की खरीद करते हैं। धनतेरस को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई वस्तुओं में 13 गुना वृद्धि होती है और हमको धन की कमी नहीं होती। मृत जीवित हो आता था विधाता के कार्य में यह बहुत बड़ा व्यवधान पड़ गया। सृष्टि में भयंकर अव्यवस्था उत्पन्न होने की आशंका के भय से देवताओं ने इन्हें छल से लोप कर दिया। वैद्यगण इस दिन धनवंतरी जी का पूजन करते हैं और वर मांगते हैं कि उनकी औषधि व उपचार में ऐसी शक्ति आ जाए जिससे रोगी को स्वास्थ्य लाभ हो। सद्गुहस्थ

इस दिन अमृत पात्र को स्मरण कर एव बर्तन घर में लाकर धनतेरस मनाते हैं। आज के दिन ही बहुत समय से चले आ रहे मनो मालिन्य को त्याग कर यमराज ने अपनी बहिन यमुना से मिलने हेतु स्वर्ग से पृथ्वी की ओर प्रस्थान किया था। गुहणियां इस दिन से अपनी देहरी पर दीपक दान करती हैं, जिससे यमराज मार्ग में प्रकाश देखकर प्रसन्न हो और उनके गृह जनों के प्रति विशेष करुणा रखें। इस वर्ष यह पर्व 29 अक्टूबर 2024 ई. मंगलवार को मनाया जा रहा है, इसी दिन प्रातः सूर्यास्त से ही त्रयोदशी तिथि का आगाज हुआ। अतः उदय व्यापिनी त्रयोदशी होने के कारण प्रदोष व्रत के साथ-साथ प्रदोष काल में दीपदान का अति विशेष महत्व रहेगा।

साथियों बात अगर हम पांच दिवसीय दीपावली महापर्व की करें तो (1) पहला दिन - पहले दिन को धनतेरस कहते हैं। दीपावली महोत्सव की शुरुआत धनतेरस से होती है। इसे धन त्रयोदशी भी कहते हैं। धनतेरस के दिन मृत्यु के देवता यमराज, धन के देवता कुबेर और आयुर्वेदचर्या धनवंतरी की पूजा का महत्व है। इसी दिन समुद्र मंथन में भगवान धनवंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे और उनके साथ आभूषण व बहुमूल्य रत्न भी समुद्र मंथन से प्राप्त हुए थे। तभी से इस दिन का नाम धनतेरस पड़ा और इस दिन बर्तन, धातु व आभूषण खरीदने की परंपरा शुरू हुई। इसे रूप चतुर्दशी भी कहते हैं।



धनतेरस से भाई दूज तक 5 दिनों के 5 त्योहार की खास बातें

(2) दूसरा दिन - दूसरे दिन को नरक चतुर्दशी रूप चौदस और काली चौदस कहते हैं। इसी दिन नरकासुर का वध कर भगवान श्रीकृष्ण ने 16,100 कन्याओं को नरकासुर के बंदीगृह से मुक्त कर उन्हें सम्मान प्रदान किया था। इस उपलक्ष्य में दीयों की बारात सजाई जाती है। इस दिन को लेकर मान्यता है कि इस दिन सूर्योदय से पूर्व उबटन एवं स्नान करने से समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन से एक ओर मान्यता जुड़ी हुई है जिसके अनुसार इस दिन विशेष रूप से रूप व सौंदर्य में वृद्धि होती है। इस दिन पांच या सात दीये जलाने की परंपरा है। इस बार यह पर्व 30 अक्टूबर 2024 बुधवार को मनाया जाएगा। (3) तीसरा दिन - अब आता है इस लड़ी के मध्य दीपावली मंत्रूषा का उल्लास और उत्साह से भरा महान पर्व दीपावली और महालक्ष्मी पूजन तीसरे दिन को दीपावली कहते हैं। यही मुख्य पर्व होता है। दीपावली का पर्व होता है। कार्तिक माह की अमावस्या को ही समुद्र मंथन से मां लक्ष्मी प्रकट हुई थीं जिन्हें धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि की देवी माना जाता है। अतः इस दिन मां लक्ष्मी के स्वागत के लिए दीप जलाए जाते हैं ताकि अमावस्या की रात के अंधकार में दीपों से वातावरण रोशन हो जाए। दूसरी मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान रामचन्द्रजी माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ

14 वर्षों का वनवास समाप्त कर घर लौटे थे। श्रीराम के स्वागत हेतु अयोध्या वासियों ने घर-घर दीप जलाए थे और नगर भर को आभायुक्त कर दिया था। तभी से दीपावली के दिन दीप जलाने की परंपरा है। 5 दिवसीय इस पर्व का प्रमुख दिन लक्ष्मी पूजन अथवा दीपावली होता है। इस दिन रात्रि को धन की देवी लक्ष्मी माता का पूजन विधिपूर्वक करना चाहिए एवं घर के प्रत्येक स्थान को स्वच्छ करके वहां दीपक लगाना चाहिए जिससे घर में लक्ष्मी का वास एवं दरिद्रता का नाश होता है। इस दिन देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश तथा द्रव्य, आभूषण आदि का पूजन करके 13 अथवा 26 दीपकों के मध्य 1 तेल का दीपक रखकर उसकी चारों बातियों को प्रज्वलित करना चाहिए एवं दीपमालिका का पूजन करके उन दीपों को घर में प्रत्येक स्थान पर रखें एवं 4 बातियों वाला दीपक रात भर जलता रहे, ऐसा प्रयास करें। (4) चौथा दिन - इस लड़ी का चौथा माणिक है कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा। यह पर्व भारत की कृषि-पूजन का पर्व होता है। कार्तिक माह की अमावस्या को ही समुद्र मंथन से मां लक्ष्मी प्रकट हुई थीं जिन्हें धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि की देवी माना जाता है। अतः इस दिन मां लक्ष्मी के स्वागत के लिए दीप जलाए जाते हैं ताकि अमावस्या की रात के अंधकार में दीपों से वातावरण रोशन हो जाए। दूसरी मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान रामचन्द्रजी माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ

विश्वकर्मा का पूजन भी श्रद्धा भक्तिपूर्वक करते हैं। आज चहुंमुखी विकास और वृद्धि की कामना से दीप जलाए जाते हैं। इस वर्ष यह पर्व 2 नवंबर 2024, शनिवार को मनाया जाएगा। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा एवं अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है। इसे पड़वा या प्रतिपदा भी कहते हैं। खासकर इस दिन घर के पालतू बैल, गाय, बकरी आदि को अच्छे से स्नान कराकर उन्हें सजाया जाता है। फिर इस दिन घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन बनाए जाते हैं और उनका पूजन कर पकवानों का भोग अर्पित किया जाता है। इस दिन को लेकर मान्यता है कि त्रेतायुग में जब इन्द्रदेव ने गोकुलवासियों से नाराज होकर मूसलधार बारिश शुरू कर दी थी, तब भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर गांववासियों को गोवर्धन की छांव में सुरक्षित किया। तभी से इस दिन गोवर्धन पूजन की परंपरा भी चली आ रही है। (5) पांचवां दिन - माला का पांचवा चमकता पर्व आता है - स्नेह, सौहार्द व प्रीति का प्रतीक यम द्वितीया अथवा भैया-दूज। इस दिन कार्तिक शुक्ल को यमराज अपने दिव्य स्वरूप में अपनी भगिनि यमुना से भेंट करने पहुंचते हैं। इस दिन को भाई दूज और यम द्वितीया कहते हैं। भाई दूज, पांच दिवसीय दीपावली महापर्व का अंतिम दिन होता है। भाई दूज का पर्व भाई-बहन के रिश्ते को प्रगाढ़ बनाने और भाई की लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है।

रक्षाबंधन के दिन भाई अपनी बहन को अपने घर बुलाता है जबकि भाई दूज पर बहन अपने भाई को अपने घर बुलाकर उसे तिलक कर भोजन कराती है और उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। इस दिन को लेकर मान्यता है कि यमराज अपनी बहन यमुनाजी से मिलने के लिए उनके घर आए थे और यमुनाजी ने उन्हें प्रेमपूर्वक भोजन कराया एवं यह वचन लिया कि इस दिन हर साल वे अपनी बहन के घर भोजन के लिए पधारेंगे। साथ ही जो बहन इस दिन अपने भाई को आमंत्रित कर तिलक करके भोजन कराएगी, उसके भाई की उम्र लंबी होगी। तभी से भाई दूज पर यह परंपरा बन गई।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि धनतेरस से दीपावली का शंखानंद, भाई दूज तक पंचदिवसीय महापर्व शुरू दीप जले दीपावली आई - 5 दिवसीय महापर्व - धनतेरस से दीपावली पर्व का आगाज। दुनियाँ के हर देश में बसे भारतवंशी धनतेरस से भाई दूज तक फिर छठ महात्योहार में खुशियों से सरोबार होंगे।

-संकलनकर्ता लेखक - कर विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतर्राष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि सीए (एटीसी) संगीत माध्यम एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र

दिवाली के दीये

दिवाली के दीये तभी होंगे सार्थक, जब रोशन होगा उस गरीब का घर। भूख से पेट नहीं काँपेगा थर-थर, ना बुझाएगा प्यास पानी दिनभर! नौकरी की तलाश में भटके दर-दर।

दिवाली के दीये तभी होंगे सार्थक, जब रोशन होगा उस गरीब का घर। नेताओं अब मत देना सिर्फ भाषण, कर देना कोई व्यवस्था देना राशन! तभी होगा मिशन दिवाली हो रोशन।

दिवाली के दीये तभी होंगे सार्थक, जब रोशन होगा उस गरीब का घर। यहीं तो हैं परीक्षा उसे भी दो सम्मान, जिस पर नहीं लक्ष्मी नहीं मेहरबान! अब मिला अवसर बनों कृपा निधान।

संजय एम. तराणेकर
(कवि, लेखक व समीक्षक)
इंदौर (मध्यप्रदेश)
98260-25986

दिवाली पर आपके घर भी पहुंच सकती है मिलावटी मिठाई

दिवाली 2024 के दौरान हम अवसर मिलावटी मिठाई खरीद लेते हैं। ऐसी मिठाइयां दोस्तों-रिश्तेदारों के जरिए आपके घर भी पहुंच जाती हैं जिससे त्योहार बीत जाने के बाद पाचन से जुड़ी कई तरह की समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। इसलिए आइए इस आर्टिकल में आपको मिठाई में होने वाली मिलावट की पहचान करने के 5 आसान तरीके बताते हैं।

नई दिल्ली। दीवाली जैसे त्योहार आते ही बाजारों में मिठाइयों की भरमार हो जाती है, लेकिन इस चकाचौंध में कई बार हम मिलावटी मिठाइयों के जाल में फंस जाते हैं। जी हां, मिलावटी मिठाइयों न केवल आपके पाचन तंत्र को खराब करती हैं बल्कि इन्हें खाने से किडनी और लिवर को भी गंभीर नुकसान पहुंचता है। इसलिए, मिठाइयों खरीदते समय सावधान रहना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं कि आप किन-किन तरीकों से मिठाई में की गई मिलावट को पहचान सकते हैं।

दिखावट और बनावट
असली मिठाइयों का रंग नेचुरल होता है। ऐसे में, अगर मिठाई का रंग बहुत चमकीला या आर्टिफिशियल हो तो सावधान हो जाएं। असली मिठाइयों का आकार एक समान होता है। अगर मिठाइयों अलग-अलग आकार की हैं

तो मुमकिन है कि उनमें मिलावट की गई हो। असली मिठाइयों मुलायम और चिकनी होती हैं, लेकिन मिठाई हार्ड या रूखी हो तो इसे खाने से बचें क्योंकि यह भी मिलावट का एक संकेत है।

स्वाद और महक
असली मिठाइयों का स्वाद नेचुरल होता है, लेकिन अगर आपको मिठाई का स्वाद बहुत मीठा या आर्टिफिशियल लगे तो संभव है कि उसमें मिलावट की गई हो। असली मिठाइयों की एक खास महक होती है, लेकिन अगर आपको मिठाई की महक अस्वाभाविक या तेज लगे तो इसे खाने से बचें क्योंकि इसमें मिलावट हो सकती है।

वाटरटेस्ट
मिठाई का एक छोटा-सा टुकड़ा तोड़कर पानी में डालकर देखें। अगर पानी का रंग बदल जाता है, जैसे कि पीला या गुलाबी हो जाता है, तो यह संकेत हो सकता है कि मिठाई में खतरनाक रंग मिलाए गए हैं।

अगर पानी में झाग आता है, तो यह संकेत हो सकता है कि मिठाई में डिटर्जेंट या अन्य केमिकल मिलाए गए हैं।

अगर पानी की सतह पर तेल की परत बन जाती है, तो यह सिग्नल हो सकता है कि मिठाई में वनस्पति तेल या अन्य तेल मिलाए गए हैं।

फायरटेस्ट
मिठाई का एक छोटा टुकड़ा लें और इसे आग



पर रखकर देखें। असली मिठाई धीरे-धीरे पिघलेगी और इसे जलने में थोड़ा समय भी लगेगा। अगर मिठाई प्योर है तो यह नेचुरल तरीके से जलेगी और इसमें से काला धुआं भी नहीं निकलेगा।

वहीं, मिलावटी मिठाई जल्दी से पिघल जाती है या जल सकती है और इसके साथ ही इसमें से

काला धुआं भी निकल सकता है।
यह तरीका भी है कारगर
दूध की मिठाई खरीदने से पहले एक छोटा-सा टेस्ट करें। मिठाई का एक टुकड़ा लेकर उसे उंगलियों से मसलें। अगर उसमें से कोई अजीब सी स्मेल आए तो सावधान हो जाएं, हो सकता है कि आपको नकली दूध वाली मिठाई मिल रही

हो।
वहीं, अगर आप मावा से बनी मिठाई खरीद रहे हैं तो इसे भी उंगलियों से मसलकर देखें और अगर इसका टेक्सचर रबड़ की तरह लग रहा है या फिर ये काफी हार्ड है, तो समझ जाएं कि इसमें भी मिलावट की गई है क्योंकि असली मावा बेहद सॉफ्ट होता है।

बिना डटे ले पाएंगे दीवाली की दावत का मजा, बस आपको रखना होगा इन 5 बातों का ख्याल

दीवाली के त्योहार की रौनक धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज तक बनी रहती है। इस दौरान स्वादिष्ट व्यंजनों (Diwali Sweets) का आनंद लेना तो लाजमी है, लेकिन लगतार तली-भुनी और मैदे वाली चीजें खाने से सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता है। पाचन संबंधी समस्याओं के साथ-साथ वजन बढ़ने की समस्या भी आम है। ऐसे में इस फेस्टिव सीजन (Festive Season) अगर आप स्वाद के साथ-साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहते हैं तो यह आर्टिकल आपके लिए ही है, क्योंकि यहां हम आपको कुछ ऐसे टिप्स (Guilt-Free Diwali Celebrations) बताते जा रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप न सिर्फ बिना मन को मारे फेस्टिवल को एनॉय कर सकते हैं बल्कि सेहत को लेकर भी बेफिक्र रह सकते हैं।

पोर्शन का ध्यान रखें
त्योहारों का समय मजे करने और अपनों के साथ वक्त बिताने का होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अपनी सेहत को नजरअंदाज कर दें। हां, स्वादिष्ट व्यंजनों का

लुप्त जरूर उठाएं, लेकिन सब्र रखना भी बेहद जरूरी है। ज्यादा खाने से न केवल वजन बढ़ता है बल्कि पाचन संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए एक ही बार में ज्यादा खाने से बचें और इन दिनों अपनी डाइट को भी बैलेंस बनाकर चले।

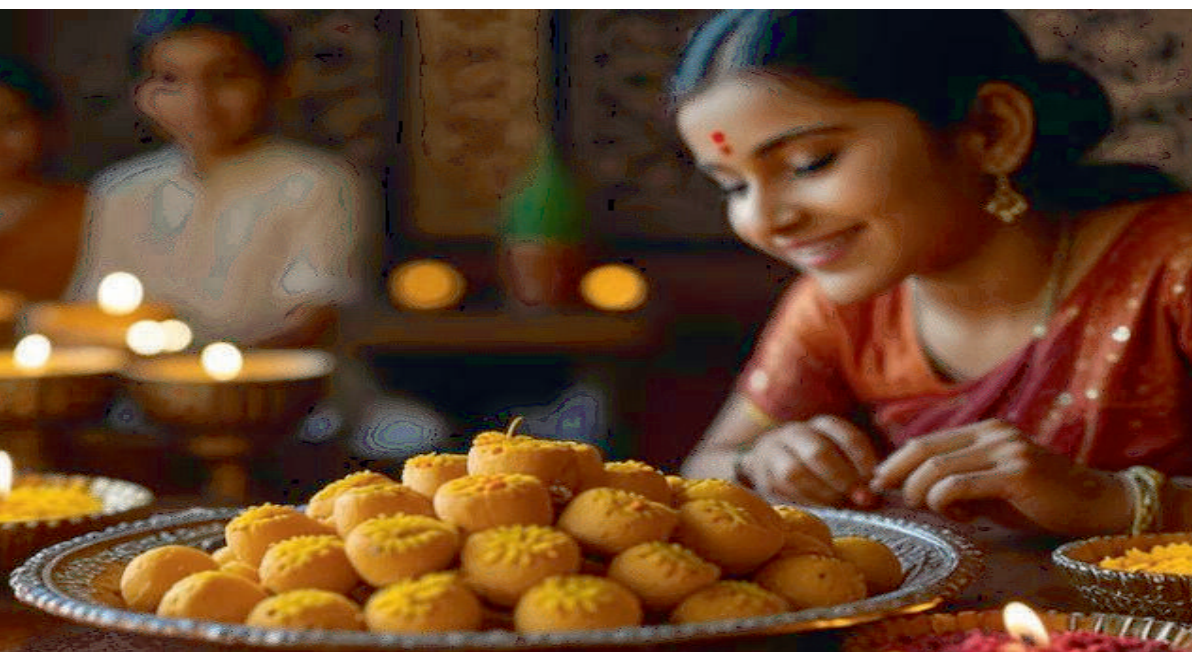
प्लानिंग है जरूरी
फेस्टिव सीजन में खाने-पीने का शौक हर किसी को होता है, लेकिन इसके साथ एक प्लानिंग भी काफी जरूरी है। त्योहारों के दौरान स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन का आनंद लेने के लिए आप अपनी थाली में लो फैट वाले प्रोटीन, साबुत अनाज, फल और सब्जियों को शामिल कर सकते हैं। साथ ही, ज्यादा कैलोरी वाली चीजों से बचकर हेल्दी रहते हुए दीवाली को एनॉय कर सकते हैं।

फिजिकली एक्टिव रहें
त्योहार के दिनों में भी अपनी फिटनेस रूटीन को न छोड़ें। नियमित रूप से योग, व्यायाम या जॉगिंग करने से न सिर्फ आपकी एक्टिव कैलोरी बर्न होगी बल्कि आप पूरे फेस्टिव सीजन के दौरान भी चुस्त और ऊर्जावान महसूस करेंगे। ये

एक्सरसाइज आपके शरीर को स्वस्थ रखने के साथ-साथ तनाव कम करने में भी मदद करेंगी।

हाइड्रेट रहें
त्योहारों के दिनों में बिजो होने के कारण अक्सर हम पानी पीना भूल जाते हैं, लेकिन याद रखें कि भरपूर पानी पीना न सिर्फ आपको हाइड्रेटेड रखेगा बल्कि डाइजेशन को दुरुस्त भी रखेगा। पानी पीने से आपकी भूख पर कंट्रोल रहेगी और आप खाने-पीने की चीजों में ओवरईटिंग नहीं करेंगे। इससे आपका पाचन तंत्र दुरुस्त रहेगा और आप त्योहारों का पूरा मजा ले पाएंगे।

हेल्दी ऑप्शंस
त्योहारों में मीठे का स्वाद तो लेना ही है, लेकिन इस बार थोड़े हेल्दी ऑप्शंस चुनें। रागी, गुड़ और देसी घी से बने पौष्टिक पंजीरी लड्डू आपके त्योहारों को और भी खास बना देंगे। रागी और ज्वार जैसे अनाज पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और पाचन में भी मददगार होते हैं। वहीं, गुड़ शरीर को एनर्जी देता है और देसी घी पाचन शक्ति को बढ़ाता है।



दीवाली का त्योहार आते ही घर भी तरह-तरह के पकवानों की खुशबू से महक उठता है। इस फेस्टिव सीजन में जश्न के साथ-साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखना बेहद जरूरी है। इस आर्टिकल में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जिनकी मदद से आप न सिर्फ स्वादिष्ट व्यंजनों का लुप्त उठा सकते हैं बल्कि सेहत को लेकर भी टेंशन फ्री रह सकते हैं।

दिल्ली में 10,000 सिविल डिफेंस वालंटियर्स रोकेंगे प्रदूषण कहां-कहां होगी तैनाती; CM आतिशी ने बताया पूरा प्लान

दिल्ली सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए 10000 सिविल डिफेंस वालंटियर्स को तैनात करेगी। इन वालंटियर्स को प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लागू करने वायु प्रदूषण की निगरानी करने और लोगों को जागरूक करने का काम सौंपा जाएगा। मुख्यमंत्री आतिशी ने बताया कि इन वालंटियर्स को दिल्ली नगर निगम दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और परिवहन विभाग की टीमों के साथ तैनात किया जाएगा।

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार 10,000 सिविल डिफेंस वालंटियर्स को तैनात करेगी। इन्हें पिछले साल बस मार्शल के रूप में काम करने के दौरान सेवा से हटा दिया गया था। अब इन्हें दिल्ली में प्रदूषण को कम करने से संबंधित उपायों को लागू करने में लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री आतिशी ने सोमवार को इसकी जानकारी दी।

आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्हें दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीडी), परिवहन विभाग और अन्य की टीमों के साथ तैनात किया जाएगा।

वायु प्रदूषण को रोकने के लिए बनी रणनीति: आतिशी
आतिशी ने बताया कि एक बैठक में अधिकारियों ने वायु प्रदूषण से निपटने में मदद के लिए शहर भर में सिविल डिफेंस वालंटियर्स और बस मार्शलों को भूमिका की रणनीति बनाई। उन्होंने कहा कि सहयोगात्मक दृष्टिकोण का उद्देश्य प्रदूषण के स्तर की प्रभावी



निगरानी और उसे कम करने के लिए कई टीमों और संसाधनों का लाभ उठाना है।

अगले हफ्ते से शुरू होगा वालंटियर्स का पंजीकरण
मुख्यमंत्री ने कहा कि 10,000 सिविल डिफेंस वालंटियर्स का पंजीकरण अगले सप्ताह किया जाएगा, जिसके बाद उन्हें अगले चार महीनों के लिए ड्यूटी सौंपी जाएगी। बस मार्शल के रूप में काम कर रहे 10,000 नगरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को पिछले साल नवंबर में हटा दिया गया था। हाल ही में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की बैठक में उन्हें चार महीने के लिए विभिन्न प्रदूषण विरोधी उपायों के लिए तैनात करने का निर्णय लिया गया था।

ग्रीन वारियर के रूप में काम करेंगे वालंटियर्स: आतिशी
उन्होंने कहा कि सिविल डिफेंस वालंटियर्स अब ग्रीन वारियर के तौर पर काम करेंगे और प्रदूषण पर लगाम लगाने की लड़ाई को सफल बनाएंगे। हमें भरोसा है कि प्रदूषण को रोकने में जो इम्पीमेंटेशन गैप था, हम इनकी मदद से उसे खत्म कर पाएंगे। आने वाले दिनों में पराली जलने, दिवाली के पटाखों और बाजारों में भीड़ के कारण जाम लगने से प्रदूषण बढ़ेगा।
बहनों की सांसें की रक्षा करेंगे वालंटियर्स: आतिशी
उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है सिविल डिफेंस वालंटियर्स पहले बहनों की रक्षा के लिए

काम करते थे, अब पूरी दिल्ली के लोगों को सांसें की रक्षा करेंगे। बढ़ते प्रदूषण के साथ दिल्ली की सीमाओं पर प्रतिबंधित वाहनों की चेकिंग के लिए इन बस मार्शलों को लगाया जाएगा।

निगरानी टीम के साथ तैनात रहेंगे वालंटियर्स: आतिशी
उन्होंने कहा कि 13 हॉट स्पॉट्स और 27 अन्य प्वाइंट्स पर जहां प्रदूषण ज्यादा रहता है, वहां नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर्स के साथ इन्हें निगरानी के लिए लगाया जाएगा। इसके अलावा MCD की निगरानी टीम के साथ इन सिविल डिफेंस वालंटियर्स और बस मार्शलों को लगाया जाएगा।

वाल्मीकि समाज शिक्षा की और अग्रसर कार्यक्रम आयोजित किया



वाल्मीकि समाज के शिक्षित मेधावी छात्र एवं समाज सेवियों को केन्द्रीय राज्य मंत्री हर्ष महतोत्रा ने किया सम्मानित

सुष्मा रानी

नई दिल्ली। वाल्मीकि जागृति मिशन (रजि.) द्वारा भगवान वाल्मीकि प्रकटोत्सव के अवसर पर शिक्षा की ओर अग्रसर वाल्मीकि समाज कार्यक्रम का आयोजन कात्यायनी सभागार मयूर विहार फेस 1 में किया गया। कार्यक्रम में वाल्मीकि समाज के शिक्षित मेधावी छात्र एवं समाज सेवियों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में हर्ष महतोत्रा सांसद पूर्वी दिल्ली एवं राज्य मंत्री भारत सरकार मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। वहीं सेवानिवृत्त कानूनी सलाहकार,

भारत सरकार डॉ. ओ. पी. शुक्ला, श्री श्री 1008 विवेक नाथ महाराज, राष्ट्रीय वाल्मीकि संत, संत सूर्या सतीश महाराज, राष्ट्रीय वाल्मीकि संत, अशोक गुप्ता, सह मंत्री, विश्व हिंदू परिषद दिल्ली प्रांत, विजय कांत पांडे, आयाम प्रमुख, विश्व हिंदू परिषद दिल्ली प्रांत, डॉ. धीरज जोशी ललित, पूर्व जिला अध्यक्ष, बिजेंद्र धामा, जिला अध्यक्ष भाजपा मयूर विहार, रामचरण गुजराती आदि गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। कार्यक्रम का आयोजन वाल्मीकि जागृति मिशन के संरक्षक राजेन्द्र पारचा और अध्यक्ष राजेश पारचा (एडवोकेट) ने किया। इस अवसर पर पूर्वी दिल्ली के सांसद और केन्द्रीय राज्य मंत्री हर्ष

महतोत्रा ने वाल्मीकि समाज के मेधावी छात्रों और विभिन्न संस्थानों में उच्च पद कार्यरत वाल्मीकि समाज के युवाओं को अवार्ड देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में ऑल इंडिया मीडिया क्लब के राष्ट्रीय महामंत्री व वरिष्ठ पत्रकार मनोज टंडन को भी पत्रकारिता के क्षेत्र में अच्छे कार्य के लिए सम्मानित किया गया। सांसद एवं मंत्री हर्ष महतोत्रा ने कहा कि वाल्मीकि समाज सनातन धर्म की रक्षा के लिए अग्र पंक्ति में खड़ा रहा है। वाल्मीकि समाज के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कार्यक्रम में आए सभी अतिथि गणों ने प्रेरित किया। इस अवसर पर मौजूद ही मौजा ग्रुप के द्वारा भगवान श्रीराम के भजनों पर संगीतमय नाट्य प्रस्तुति भी की गई।

अब इसे 'जमैका मार्ग' कहिए, दिल्ली के इस रोड का बदल रहा है नाम; MCD ने पारित किया प्रस्ताव

परिवहन विशेष न्यूज

उच्चायुक्त ने 20 सितंबर को अपने बाद के ईमेल में उक्त सड़क का नाम मार्क्स गवें मार्ग के बजाय जमैका मार्ग रखने का प्रस्ताव रखा था। अपनी सहमति जताते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा था कि जमैका सरकार द्वारा अर्थशास्त्री समाज सुधारक और राजनीतिक नेता डॉ. बी.आर. अंबेडकर को दिए गए सम्मान के बदले में वसंत विहार में बी-9 लेन/रोड का नाम जमैका मार्ग रखा जा सकता है।

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने सोमवार को सदन की बैठक में प्रस्ताव पारित कर दक्षिणी दिल्ली के वसंत विहार इलाके के एक मार्ग का नाम बदलकर 'जमैका मार्ग' कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि वसंत मार्ग पर बी-9 रोड (हाउस नंबर 7, वसंत मार्ग) से बी-8 स्ट्रीट (हाउस नंबर बी-8/26), वसंत विहार तक के मार्ग का नाम अब बदलकर जमैका मार्ग किया जाएगा। इसका वर्तमान नाम जमैका के पहले राष्ट्रीय नायक और कार्यकर्ता मार्क्स मोसिया गाँव के सम्मान में मार्क्स गवें मार्ग है।

कैरिबियाई देश के साथ भारत के संबंध होंगे और बेहतर
सड़क का प्रस्तावित नाम बदलने को दोनों देशों और उनके लोगों के बीच मजबूत सद्भावना के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। इसमें कहा गया है कि इसका उद्देश्य उनके द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और कैरिबियाई देश के साथ भारत के विश्वास और दोस्ती का एक अदृष्ट बंधन बनाना है।

जमैका के उच्चायोग ने नाम बदलने का रखा था प्रस्ताव

इसमें कहा गया है, रिकॉर्ड में डॉ. बी.आर. अंबेडकर का नाम बदलकर डॉ. बी.आर. अंबेडकर के नाम पर रखने के संबंध में पारस्परिकता को भी ध्यान में रखा गया है। वसंत विहार में विदेश मंत्रालय (एम्ईए) और एमसीडी को लिखे एक पत्र में जमैका के उच्चायोग ने सड़क का नाम बदलकर जमैका मार्ग रखने का प्रस्ताव रखा था।

जमैका में एक सड़क का नाम अंबेडकर के नाम पर

प्रस्ताव में कहा गया है, उच्चायुक्त ने 20 सितंबर को अपने बाद के ईमेल में उक्त सड़क का नाम 'मार्क्स गवें मार्ग' के बजाय 'जमैका मार्ग' रखने का प्रस्ताव रखा था। जमैका उच्चायोग ने विदेश मंत्रालय को भी यही बात बताई है। अपनी सहमति जताते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा, जमैका सरकार द्वारा भारतीय न्यायविद, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और राजनीतिक नेता डॉ. बी.आर. अंबेडकर को दिए गए सम्मान के बदले में वसंत विहार में बी-9 लेन/रोड का नाम 'जमैका मार्ग' रखा जा सकता है।

भलस्वा में भी बदला रोड का नाम
इसके अतिरिक्त, एमसीडी ने वार्ड 17 के अंतर्गत भलस्वा फ्लाईओवर से आईटीआई रोड, जहांगीरपुरी और हरिजन कॉलोनी तक मुख्य सड़क का नाम क्षेत्र के एक सामाजिक कार्यकर्ता और भलस्वा गाँव के पूर्व प्रधान स्वर्गीय गोकुल चंद मार्ग के सम्मान में रखने का प्रस्ताव पारित किया है।

एमसीडी की सदन की बैठक में विपक्ष ने किया हंगामा

सुष्मा रानी

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम की बैठक आज रही हंगामे के नाम, दलित मेयर के चुनाव को लेकर आज एमसीडी सदन में जमकर हंगामा हुआ। सदन की बैठक के शुरू होते ही विपक्ष के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष के हंगामे के चलते मेयर डॉ. शैली ओबेरॉय ने सदन की बैठक को अगली तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगले सदन में मेयर चुनाव कराए जाएंगे।

इस बीच, कई महत्वपूर्ण एजेंडा को पास किया गया और कुछ प्रस्तावों को टाल दिया गया। इस दौरान बैठक में भाजपा के पार्षदों ने मेयर को कई मुद्दों पर घेरा और साथ ही भाजपा पार्षदों ने मेयर पर किसी कार्यक्रम में ब्राजील जाने का भी आरोप लगाया। साथ ही भाजपा के पार्षदों ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कई आरोप लगाए।

भाजपा पार्षदों के हंगामे के बीच अनुसूचित जाति (एससी) के महापौर पद के उम्मीदवार किशन लाल जंजीरों में हाथ ऊपर करके अपना विरोध जताते नजर आए। वह भाजपा के शकूर बस्ती वार्ड से इस वर्ष अप्रैल में महापौर (एससी) के लिए उम्मीदवार बनाए गए थे। दिल्ली नगर निगम के नियम अनुसार इस वर्ष मेयर पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है।

17 ही भाजपा ने महापौर शैली ओबेरॉय के



ब्राजील दौरे पर सवाल उठा रही है। अब तक निगम की 30 से ज्यादा बैठकें हो चुकी हैं, जिसमें 28 बैठकें हंगामे की भेंट चढ़ गईं।

उल्लेखनीय है कि आतिशी के सीएम बनने के बाद महापौर चुनाव में आ रही अड़न खत्म हो गई थी। ऐसे में संभावना जताई जा रही थी कि अक्टूबर में होत वाली सदन की बैठक में महापौर का चुनाव हो जाएगा।

निगम ने इस चुनाव के लिए मंजूरी भी मांगी थी, लेकिन महापौर ने त्योहारी मौसम को देखते

हुए पार्षदों की व्यस्तता का हवाला देते हुए मंजूरी नहीं दी। हाल ही में भाजपा ने महापौर कार्यालय के बाहर भी प्रदर्शन किया था।

स्थायी समिति नहीं बनी तो चार लाख स्ट्रीट लाइटों पर संकट

दिल्ली में स्थायी समिति का गठन न होने की वजह से निगम की कई परियोजनाओं में दिक्कत आ रही है। आगामी दो माह में स्थायी समिति का गठन नहीं हुआ तो चार लाख स्ट्रीट लाइटों पर संकट आ जाएगा, क्योंकि इन स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत

और रखरखाव का कार्यदिसंबर में खत्म हो रहा है। ऐसे में टेंडर खत्म होने तक नई कंपनी का चयन नहीं हुआ तो स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत और नए स्थान पर स्ट्रीट लाइट लगाने में काफी दिक्कत होगी। खास तौर पर यह दिक्कत पूरकालिक दक्षिणी निगम के अधीन आने वाले चार जोन मध्य, दक्षिणी, पश्चिमी और नजफगढ़ जोन में होगी। इससे बचने के लिए एमसीडी ने पूर्व में ही तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन स्थायी समिति का गठन नहीं हुआ तो समस्या बढ़ना तय है।

विनय मिश्रा ने दिल्ली जल बोर्ड उपाध्यक्ष का चार्ज संभाला, केजरीवाल के मार्गदर्शन में दिल्ली वालों को स्वच्छ व मुफ्त जल मुहैया कराने की जताई प्रतिबद्धता

सुष्मा रानी

नई दिल्ली। आप विधायक विनय मिश्रा से सोमवार को औपचारिक रूप से दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष का पद संभाल लिया। इसी के साथ ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन में दिल्लीवासियों को स्वच्छ पानी और मुफ्त जल उपलब्ध करने का भरोसा दिलाया है। इस अवसर पर विनय मिश्रा ने कहा कि भाजपा ने अपनी गंदी राजनीति के चलते डीजेबी को एक साल से अपंग बना दिया था, पानी की सप्लाई और सीवर की सफाई के काम ठप्प कर दिए थे। केजरीवाल के दिशानिर्देश में फिर पटरी पर लौटया जल बोर्ड, हम दिल्लीवासियों को पानी और सीवर की समस्या को जल्द हल कर देंगे। छठ पूजा हमारे लिए एक बहुत बड़ा आयोजन है, आप सरकार हर साल की तरह इस बार भी यमुना नदि पर छठ पूजा के अच्छे इंतजाम करेगी। हरियाणा में जलने वाली पराली और वहां से यमुना में छोड़े जाने वाले इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से दिल्ली में वायु और जल प्रदूषण हो रहा है। मैंने सीएम आतिशी से अपील की है कि वह हरियाणा सरकार से बात करके वहां से आ रहे इंडस्ट्रियल वेस्ट को रोकवाए ताकि हम दिल्ली वालों को साफ पानी मिल सके।

इस दौरान विनय मिश्रा ने कहा कि दिल्ली पिछले एक साल से चुनौतियों का सामना कर रही है। इन्होंने दिल्ली के कामों को रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे पहले इन्होंने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री को गिरफ्तार करवाया और फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार करवाया ताकि दिल्ली के विकास कार्यों को रोका जा सके। पिछले एक साल से इन्होंने हर विभाग के काम में अड़नप डाली है, चाहे वह विधवा पेंशन हो, डॉक्टरों की तनखाह हो, मांशला क्लीनिक में टेस्ट हो, दवाई हो,



अस्पतालों में डेटा एंटरि ऑपरेटर्स की नौकरी हो या बस मार्शल की नियुक्ति हो। इन्होंने सबको बर्खास्त करके काम रोकने की पूरी कोशिश की है। दिल्ली जल बोर्ड को भी इन्होंने पिछले एक साल से अपंग कर दिया था। न तो पानी की सप्लाई सही से करने दे रहे हैं और न सीवर की सफाई होने दे रहे हैं। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए हैं और उनके आने के बाद दिल्ली में युद्ध स्तर पर काम हो रहे हैं। सड़कों की मरम्मत की जा रही है, और अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर अब दिल्ली जल बोर्ड भी बहुत जल्द पटरी पर आ जाएगा। सीवर और पानी की समस्याओं को हम जल्द ही हल कर देंगे।

उन्होंने कहा कि हरियाणा में पराली जलाने की वजह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है। अरविंद केजरीवाल से नफरत करते-करते भाजपा अब दिल्ली के लोगों से भी नफरत करने लग गई है। पराली के धुएँ के बाद अब हरियाणा से आने वाले

इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से यमुना में अमोनिया का स्तर इतना बढ़ गया है। हर साल 12 से लेकर 31 अक्टूबर तक मेटेनॉस की वजह से गंग नहर बंद रहती है, जिसके कारण हमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में यमुना से पानी लेना पड़ता है। लेकिन अमोनिया का स्तर अधिक होने की वजह से हमारे प्लांट अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहे हैं। रिवर को मैन सॉनिया डब्यूटीपी का दौरा भी किया था, जिसमें हमने पाया कि अमोनिया का स्तर 0.9 पीपीएम था, जो कि बहुत खतरनाक है। मैं मुख्यमंत्री आतिशी से मिलकर अपील की है कि वह हरियाणा सरकार से बात करे और हरियाणा से यमुना नदी में छोड़े जा रहे इंडस्ट्रियल वेस्ट को तुरंत रोकवाए ताकि हम दिल्ली के लोगों को साफ पानी उपलब्ध करवा सकें।

विनय मिश्रा ने कहा कि यमुना में झाग वाली तस्वीरें हरियाणा की तरफ की थीं। भाजपा के अध्यक्ष ने जब यमुना में डुबकी लगाई, तब कोई

झाग नहीं दिखा। ये लोग केवल प्रोपगेंडा फैलाते हैं। दिल्ली सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। छठ पूजा हमारे लिए एक बहुत बड़ा आयोजन है और सरकारी स्तर पर हर घाट पर टेस्ट, साउंड स्टम्प कर रहे हैं। हमने व्यवस्थाएं की जाती हैं। यमुना पर भी छठ पूजा के लिए बेहतर इंतजाम कराए जाएंगे।

विनय मिश्रा ने कहा कि आनंद विहार में आने वाली डीजल बसों से भी प्रदूषण हो रहा है। अगर हरियाणा और बाकी पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं को कम किया जाए, तो दिल्ली के वायु प्रदूषण में सुधार हो सकता है। जब से भाजपा केंद्र सरकार में आई है, उसने केवल काम रोके हैं। हमने प्रदूषण के कारणों का पता लगाने के लिए आईटी विशेषज्ञों को रियल टाइम असेसमेंट पर लगाया था, लेकिन इन्होंने उनकी पेमेंट तक रोक दी। किंडे सरकार प्रदूषण के मुद्दे पर गंभीर नहीं है। पेंडिंग सवाल अगस्त में प्रदूषण को लेकर उच्चस्तरीय बैठक हो गई थी, जिसकी वजह से काम तेजी से हो रहे थे। लेकिन इस साल की बैठक अभी कुछ ही दिनों पहले हुई है। इनकी मंशा काम करने की नहीं, बल्कि केवल काम रोकने की है। जनता देख रही है कि देश के 22 राज्यों में इनकी सरकार है, लेकिन ये कहीं भी काम नहीं कर रहे और सिर्फ दिल्ली सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी वायु गुणवत्ता सूचकांक उच्च स्तर पर है। इन राज्यों में बिजली महंगी है और पानी की भी समस्या है। दिल्ली सरकार इन चीजों को लेकर काफी गंभीर है और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में काम कर रही है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कुंजिम बारिश कराने की भी बात कही है। अगर केंद्र सरकार इस पर सकारात्मक रुख अपनाती है, तो हम जल्द ही दिल्ली को प्रदूषण से मुक्ति दिलाने में सक्षम हो पाएंगे।

पराली के समाधान पर भाजपा की सरकारों का योगदान शून्य है वहीं आप सरकार ने पंजाब में 77 फीसद कमी की है- दिलीप पांडे

सुष्मा रानी

नई दिल्ली। भाजपा शासित उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकारों को पराली के समाधान के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार से सीखना चाहिए। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों के कारण वहां पराली जलाने के मामले काफी कम हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप पांडे ने कहा कि पंजाब सरकार ने पराली की समस्या से निपटने के लिए कई सारे प्रमुख कदम उठाए।

उन्होंने कहा कि आंकड़े बताते हैं कि पराली के मामले में किस तरह से पंजाब की सरकार ने जमीन से आसमान तक का सफर तय किया है। 2022 के अक्टूबर के इसी सप्ताह के आंकड़े के अनुसार, पंजाब में पराली जलाने के 8 हजार मामले रिपोर्ट किए गए थे। वहीं, 2024 में सिर्फ 1866 मामले रिपोर्ट किए गए हैं। इस मामले पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप पांडे ने सोमवार को पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर कहा कि पंजाब की सरकार ने काबिल ए तारीफ काम किया है और भाजपा शासित राज्यों को पंजाब सरकार के इन प्रयासों से सिखना चाहिए। साथ ही, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकारें आरोप-प्रत्यारोप करने में लगी रहें। देश के लोग देख रहे हैं कि पराली जलाने के मामलों को कम करने में भाजपा की सरकारों का योगदान शून्य है।

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप पांडे ने सोमवार को पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार से निपटने के लिए कई सारे प्रमुख कदम उठाए। एक अलग क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट सिस्टम को स्थापित किया। यह सिस्टम काम करता रहे इसके लिए पांच सौ करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बजट बनाया। श्री टायर मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया। पराली की समस्या संज्ञान लेने के लिए इन

इन सीटू और एक्स सीटू दोनों तरह के मैनेजमेंट के तरीके अपनाए। जिसका नतीजा यह रहा कि आज पिछले कई सालों के निरंतर प्रयास के बाद बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव देखने को मिल रहा है। पराली, जो एक बड़ी आपदा-विपदा थी, उसको काफी हद तक पंजाब की सरकारों ने एड्रेस करने में सफलता पा ली है। जबकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आरोप-प्रत्यारोप करने में लगी रहें।

उन्होंने कहा कि आंकड़े बताते हैं कि पराली के मामले में किस तरह से पंजाब की सरकार ने जमीन से आसमान तक का सफर तय किया है। 2022 के अक्टूबर के इसी सप्ताह के आंकड़े के अनुसार, पंजाब में पराली जलाने के 8 हजार मामले रिपोर्ट किए गए थे। वहीं, 2024 में सिर्फ 1866 मामले रिपोर्ट किए गए हैं। इस मामले पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप पांडे ने सोमवार को पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर कहा कि पंजाब की सरकार ने काबिल ए तारीफ काम किया है और भाजपा शासित राज्यों को पंजाब सरकार के इन प्रयासों से सिखना चाहिए। साथ ही, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकारें आरोप-प्रत्यारोप करने में लगी रहें। देश के लोग देख रहे हैं कि पराली जलाने के मामलों को कम करने में भाजपा की सरकारों का योगदान शून्य है।

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप पांडे ने सोमवार को पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार से निपटने के लिए कई सारे प्रमुख कदम उठाए। एक अलग क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट सिस्टम को स्थापित किया। यह सिस्टम काम करता रहे इसके लिए पांच सौ करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बजट बनाया। श्री टायर मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया। पराली की समस्या संज्ञान लेने के लिए इन

उन्होंने कहा कि आंकड़े बताते हैं कि पराली के मामले में किस तरह से पंजाब की सरकार ने जमीन से आसमान तक का सफर तय किया है। 2022 के अक्टूबर के इसी सप्ताह के आंकड़े के अनुसार, पंजाब में पराली जलाने के 8 हजार मामले रिपोर्ट किए गए थे। वहीं, 2024 में सिर्फ 1866 मामले रिपोर्ट किए गए हैं। इस मामले पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप पांडे ने सोमवार को पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर कहा कि पंजाब की सरकार ने काबिल ए तारीफ काम किया है और भाजपा शासित राज्यों को पंजाब सरकार के इन प्रयासों से सिखना चाहिए।

उन्होंने कहा कि आंकड़े बताते हैं कि पराली के मामले में किस तरह से पंजाब की सरकार ने जमीन से आसमान तक का सफर तय किया है। 2022 के अक्टूबर के इसी सप्ताह के आंकड़े के अनुसार, पंजाब में पराली जलाने के 8 हजार मामले रिपोर्ट किए गए थे। वहीं, 2024 में सिर्फ 1866 मामले रिपोर्ट किए गए हैं। इस मामले पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप पांडे ने सोमवार को पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर कहा कि पंजाब की सरकार ने काबिल ए तारीफ काम किया है और भाजपा शासित राज्यों को पंजाब सरकार के इन प्रयासों से सिखना चाहिए।

वीके अग्रवाल समेत पांच प्रत्याशियों के नामांकन पत्र खारिज, एक की उम्र निकली दो साल कम

गाजियाबाद शहर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में कितने प्रत्याशी मैदान में है इसका निर्णय सोमवार को हो गया है। इस सीट पर अब तक कुल 19 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है नामांकन पत्रों की जांच के बाद पांच प्रत्याशियों का नामांकन पत्र खारिज हो गया है। इन लोगों को नामांकन पत्र में खामियां थी। इसलिए इन प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा।

परिवहन विशेष न्यूज

गाजियाबाद। गाजियाबाद शहर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में दखिल किए गए 19 में से पांच प्रत्याशियों के नामांकन पत्र खारिज कर दिए गए हैं। अब 14 प्रत्याशी मैदान में बचे हैं। मंगलवार से नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे।

किस पार्टी से कौन लड़ रहा चुनाव ?
नामांकन पत्र वापसी की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर है। गाजियाबाद शहर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा ने संजीव शर्मा, सपा ने सिंह राज जाटव, बसपा ने पीएन गर्ग को प्रत्याशी बनाया है।

इन लोगों ने किया नामांकन
भाजपा से संजीव शर्मा
सपा से सिंह राज जाटव
बसपा से पीएन गर्ग
असदुद्दीन आवैसी की पार्टी एआइएमआइएम से रवि गौतम
आजाद समाज पार्टी से सत्यपाल चौधरी
हिंदुस्थान निर्माण दल से पिंकी चौधरी की पत्नी पूनम
राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी (सत्य) से धर्मेन्द्र सिंह
सम्राट मिहिर भोज समाज पार्टी से पवन राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी से गयादीन अहिरवाल
अखिल भारतीय आर्य सभा से सोम प्रताप गहलोत
ब्लिक पार्लिटिकल पार्टी से वीरेंद्र कुमार
सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी से रवि



कुमार पांचाल
बतौर निर्दलीय प्रत्याशी सत्यम, विनय कुमार शर्मा, मिथुन जायसवाल, कुलभूषण त्यागी, रुपेश चंद्र, वीके अग्रवाल और शमसेर राणा ने नामांकन किया था।
इनमें से सोमवार को वीके अग्रवाल, कुलभूषण

त्यागी, सोम प्रताप गहलोत, वीरेंद्र कुमार और सत्यम शर्मा का नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया है।
रिटनिंग अधिकारी डॉ. संतोष उपाध्याय ने बताया कि नामांकन पत्र दखिल करने वाले प्रत्याशी सत्यम की उम्र 23 साल थी, जबकि विधानसभा

चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की 25 साल की उम्र होना अनिवार्य है। इनके अलावा अन्य चार प्रत्याशियों के नामांकन पत्र में त्रुटियां मिली हैं। इस कारण पांच प्रत्याशियों के नामांकन पत्र खारिज किए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि गाजियाबाद शहर सहित यूपी

वर्ष 2022			
कुल मतदान	पुरुष मतदाता	महिला मतदाता	
2,44,908	1,36,406	1,07,588	
चुनाव परिणाम			
	भाजपा	अतुल गर्ग	1,50,205
	सपा	विशाल वर्मा	44,668
	बसपा	कृष्ण कुमार	32,691
	कांग्रेस	सुशांत गौयल	11,818

की नौ विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे।
शहर विधायक चुनने के लिए 4.61 लाख मतदाता करेंगे मतदान
गाजियाबाद शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में विधायक चुनने के लिए 13 नवंबर को

4.61 लाख मतदाता 506 मतदेय स्थल पर मतदान करेंगे। मतदान के लिए कुल जिले में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने के लिए जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। चुनाव को लेकर अपराजिलाधिकारी नगर गंभीर सिंह को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

350 रुपये का समोसा... 16,400 की एक गिलास कोल्ड ड्रिंक; डेटिंग के नाम पर युवती ने शख्स को लूटा

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हनीट्रैप के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। पांच युवतियां युवकों को डेटिंग एप के माध्यम से फंसाती थीं। इसके बाद मिलने के बहाने उनसे जबरन वसूली की जाती थी। विरोध करने पर बंधक बनाकर पीटा जाता था। दिल्ली के एक युवक की सजाता से पूरे रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। आरोपियों ने अभी तक कई लोगों को अपना शिकार बनाया है।

गाजियाबाद। गाजियाबाद में हैनीट्रैप मामले में बड़ा खुलासा है। आरोपी युवतियां पिछले एक साल से युवकों को जाल में फंसाती थीं जो अंजाम दे रही थीं। 21 अक्टूबर को भी युवतियों ने एक युवक को मिलने बुलाया। उसके पहुंचने पर कैफे में भारी भरकम बिल थमा दिया गया। विरोध करने पर बिल चुकाने का दबाव बनाया। मगर पुलिस के पहुंचते ही हनीट्रैप के इस पूरे खेल से पर्दा उठ गया। पुलिस ने पांच युवतियों समेत आठ लोगों को गिरफ्तार किया है।

टाइगर कैफे जाना पड़ा भारी
21 अक्टूबर को दिल्ली में रहने वाले एक युवक को युवती ने गाजियाबाद के कौशांबी डेट पर बुलाया। यहां युवक को कोल्ड ड्रिंक के लिए 16,400 रुपये चुकाने पड़े। दरअसल, युवतियां डेटिंग एप के माध्यम से युवकों को अपने जाल में फंसाती थीं। इसके बाद कौशांबी मेट्रो स्टेशन के पास स्थित टाइगर कैफे में मिलने बुलाती। युवती के झांसे में दिल्ली का युवक भी आ गया और उससे मिलने गाजियाबाद के टाइगर कैफे पहुंचा।



350 रुपये चुकाने को कहा
एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक कैफे में कोई साइनबोर्ड नहीं था। ऑनलाइन भी इसका कोई जिक्र नहीं मिला। लोकेशन नोट करने के बाद युवक को कुछ संदेह हुआ। उसने तुरंत अपनी लाइव लोकेशन अपने दोस्त को भेज दी और उसे मैसेज भी कर दिया। लड़की से मिलने के बाद जब युवक जाने लगा तो कोल्ड ड्रिंक के एक गिलास का बिल 16,400 रुपये उसके सामने रखा गया। युवक ने भारी-भरकम बिल का विरोध किया। इसके बाद आरोपियों ने युवक को वहीं जबरन रोके रखा गया और उससे 50 हजार रुपये का भुगतान

करने को कहा। लाइव लोकेशन के आधार पर कुछ समय पर पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। इसके बाद हनीट्रैप के बड़े राज से पर्दा उठ गया। पांचों लड़कियां दिल्ली की रहने वाली हैं और 12वीं पास हैं। सभी डेटिंग एप पर सक्रिय हैं। डेटिंग एप के माध्यम से ही पुरुषों से संपर्क करती थीं। बात आगे बढ़ने पर टाइगर कैफे मिलने बुलाती और यहां भारी-भरकम बिल के नाम पर जबरन वसूली की जाती।
350 रुपये में मिलता था एक समोसा
आरोपी अब तक कई लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। उनसे लाखों रुपये की ठगी भी की। कैफे में एक समोसा 350 रुपये का मिलता था। मनमाना बिल न देने पर मारपीट भी की जाती थी। युवतियों को हर टेबल के बिल का 25 फीसदी मिलता था। दो आरोपियों ने एक साल के एप्रैम में 50 हजार रुपये किराये पर जगह ली थी। इसके बाद यहां टाइगर कैफे खोला।

सावधान : अगर आप धार्मिक स्थल गंगाजी राजघाट नरौरा स्नान करने जा रहे हैं तो चोरों से सतर्क रहें

गंगाजी राजघाट नरौरा पर नकली पंडे, कुछ दुकानदार और बाइकर गैंग मिलकर करते हैं महिलाओं का क्रीमती सामान चोरी
धार्मिक स्थल पर चोरों का गैंग स्नान करने आये श्रद्धालुओं के मोबाइल, पैसे और अन्य क्रीमती समान पलक झपक ही कर लेते हैं चोरी

यूपी, संजय सागर सिंह। बुलन्दशहर के नरौरा धार्मिक स्थल गंगाजी राजघाट पर अपनों का पिंडदान करने एवं स्नान करने आये महिला पुरुष श्रद्धालुओं के मोबाइल, पैसे और अन्य क्रीमती समान चोरी होने के लगातार मामले प्रकाश में आ रहे हैं। यहां की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। धार्मिक स्थलों पर ऐसी गतिविधियां न केवल श्रद्धालुओं के लिए खतरनाक हैं, बल्कि समाज के लिए भी हानिकारक हैं।

इस संदर्भ में उपासना सिंह ने बताया कि हम अपने परिवार के साथ अपने मामाजी का पिंडदान आये थे। यहां के पंडे शर्ट पहने नकली पंडे ने पहले तो पिंडदान किया उसके बाद अपना सनाप पैसे मांगकर हमारा ध्यान भटकवा दिया और ध्यान भटकते ही नकली पंडे, ने अपने गैंग के साथ मिलकर हमारा मोबाइल एक पीली टीशर्ट पहने लड़के के द्वारा चोरी करा दिया और चोर को पकड़ने के बजाय सभी शांति नकली पण्डे बेशर्मी से हँसकर बोले मैं डेम परेशान मत होइए यहां तो ये रोज की बात है,



समझ लीजियेगा की आप ने मोबाइल गंगा जी में दान कर दिया। यह चोरी चकारी के काम शांति नकली नकली पंडे, कुछ दुकानदार और बाइकर गैंग सब मिलकर करते हैं और वहीं, बहुत ही हैरत की बात यह है कि इतने बड़े धार्मिक घाट पर एक भी महिला या पुरुष पुलिस कर्मी मौजूद नहीं था। जब चोरी की शिकायत करने हम करीब एक किलोमीटर की दूरी पर बनी चोरी कर गये तो वहां कोई भी मौजूद नहीं था। उसके बाद दूसरे के फोन से 112 नम्बर पर फोन किया तो दूसरे थाने की पुलिस घाट पर आयी लेकिन सम्बन्धित चोरी पर कोई पुलिस कर्मी मौजूद नहीं था। हमारा योगी महाराज जी निवेदन हैं कि महिला सुरक्षा के अभाव में धार्मिक क्षेत्र की कानून व्यवस्था का जायजा लेकर पीली टीशर्ट पहने लड़के के द्वारा चोरी करा दिया जिससे धार्मिक घाट पर सुरक्षा का माहौल बना रहे।

पूजा शर्मा ने बताया कि अगर आप गंगाजी

के राजघाट पर स्नान करने जा रहे हैं, तो चोरों से सतर्क रहें। सावधानी बरतें। सतर्क रहकर ही अपने सामान की सुरक्षा करें। क्यूकी यहां कानून व्यवस्था पूरी तरह से भंग है। यहाँ नकली पंडे, कुछ दुकानदार और बाइकर गैंग मिलकर महिलाओं के पर्स से पैसे चोरी कर रहे हैं। ये गैंग स्नान करने आए लोगों के मोबाइल, पैसे और अन्य कीमती सामान को पल भर में चुरा लेते हैं। यहां की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। धार्मिक स्थलों पर ऐसी गतिविधियां न केवल श्रद्धालुओं के लिए खतरनाक हैं, बल्कि समाज के लिए भी हानिकारक हैं। राजघाट, नरौरा में गंगाजी के किनारे धार्मिक स्थल पर कुछ असामाजिक तत्वों की गतिविधियां चिंता का विषय हैं। यहां आये दिन चोरियां होती रहती हैं, कोई देखने व सुनने वाला नहीं है। यहां के नकली पंडे, कुछ दुकानदार और बाइकर गैंग मिलकर दूर दराज से आए श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं। धार्मिक स्थल पर

एक-एक बाइकर पर चार-चार असामाजिक तत्व घूमते रहते हैं इन्हें कोई रोकने या टोकने वाला नहीं, यह असामाजिक तत्व स्नान कर रही लड़कियों और महिलाओं पर गन्दी नजर रखते हैं, धाट पर महिलाओं की सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। वहीं, यह कुछ नकली पण्डे शराब का सेवन कर घाट पर रखे तख्तों व गंगा जी के किनारे पर लेटे रहते हैं। कभी भी कोई बड़ी घटना घट सकती है, और इससे समाजान धर्म की छवि को नुकसान पहुंचाने की आशंका है। हमारी अपील है कि इस मुद्दे का समाधान करने के लिए स्थानीय प्रशासन और पुलिस को सक्रियता से असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित वातावरण मिल सके और धार्मिक स्थलों की गरिमा बनी रहे। साथ ही, जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थानीय समुदाय को भी सुरक्षा पर विशेष में संवेदनशील होना आवश्यक है।

आखिर हिंदुओं की पार्टी 'भाजपा' गाजियाबाद में वैश्यों और ब्राह्मणों के ही इर्दगिर्द क्यों घूम रही है, पूछते हैं लोग!

कमलेश पांडे

भाजपा को सियासत में चाहे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हों या फिर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इसके अपवाद नहीं हैं। इसलिए गाजियाबाद भाजपा के शह-मात के खेल को समझते रहिए, जिसका असली एग्जांपल आरएसएस से जुड़ा कोई छुपा रूस्तम होता है।
आखिर हिंदुओं की पार्टी 'भाजपा' गाजियाबाद में वैश्यों और ब्राह्मणों के ही इर्दगिर्द क्यों घूम रही है, गाजियाबाद विधानसभा उपचुनाव के बहाने एक बार फिर से पूछ रहे हैं लोग। कुछ यही सवाल लोकसभा चुनाव 2024 में भी उठ चुका था। क्योंकि महानगरीय जनपद में अपने हिन्दू जनताधर को ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देने में भाजपा जानाथसिंह को संतुष्ट करने में एक बार फिर मात खा चुकी है, इसके बावजूद कि यह पार्टी का अभेद्यकिला है।
आखिर ऐसा क्यों? कहीं वैश्यों के 'मनी पॉवर' और ब्राह्मणों के 'प्रशासनिक व संगठनात्मक कौशल' के आगे अन्य जातियों के नेता फिसलू तो साबित नहीं हो रहे! या फिर कोई और बात है। वैसे तो क्षत्रिय समाज से आने वाले जनरल वी के सिंह ने गाजियाबाद में बीते 10 सालों में अच्छी पकड़ बना ली थी और अपनी जाति के पार्षदों को भी खूब प्रमोटे किया। लेकिन अचानक उन्हें सियासी हाशिये पर इसलिए धकेल दिया गया, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पीएन नरेंद्र मोदी के बीच बेहतर समन्वय स्थापित नहीं कर पाए।
हाल ही में जिस तरह से उन्होंने अपना टिकट काटे जाने को लेकर पीएमओ से सांजिश होने की बात कही है, उससे गाजियाबाद सदर उपचुनाव में उनकी रही सही सजावनाएँ भी खत्म हो गईं। दरअसल, राजनीति में कहा जाता है कि बड़े नेता सिर्फ दो ही तरह के पार्षदों को पसंद करते हैं- या तो आपसर्पित और सार्वभूमिक कार्यकर्ता हैं, या फिर धनाढ्य हैं। क्योंकि पार्टी विस्तार से लेकर चुनावी जीत तक में इनकी ही प्रत्यक्ष व परोक्ष भूमिका रहती है।
इसके अलावा, पार्टी में ऊंचे पदों पर बहुराज्य होते रहने वाली पतंगबाजी में भी उपयुक्त दोनों प्रकार के नेता ही भरसे के काबिल निकलते हैं। क्योंकि पार्षद क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र या संसदीय क्षेत्र में थोड़ा भी जानाधार रखने वाले नेता स्वभाव वश ही सही पर बड़े नेताओं को

बंटोगे तो कटोगे का पाठ पढ़ाने वाले नेता टिकट या पार्टी दायित्व के बंटवारे में सवर्ण, ओबीसी और दलित समाज को समान प्रतिनिधित्व या दायित्व क्यों नहीं देते? एक ही जाति से केंद्र में पीएम और जनपद में महापौर और सांसद देना का क्या औचित्य है? जबकि राज्य में एक ही जाति के सीएम होने के चलते गाजियाबाद संसदीय सीट से उनकी जाति के पर कतरे गए।
आरोप तो यह भी है कि गाजियाबाद में सांसद का पद यहां क्षत्रिय और वैश्य समाज के इर्दगिर्द घूम रहा है, वहीं, पार्टी के पांच विधायकों में एन सी, एक गुर्जर के अलावा दलितों, यादवों, लवकुश आदि को कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, जबकि दो ब्राह्मण विधायकों (ब्राह्मण और त्यागी ब्राह्मण) के रहते हुए तीसरे ब्राह्मण से संजीव शर्मा, महानगर अध्यक्ष, गाजियाबाद भाजपा को भी गाजियाबाद विस उपचुनाव का टिकट थमा दिया गया।
कहा जा रहा है कि उन्हें सांसद अतुल गर्ग, कबीना मंत्री सुनील शर्मा के अलावा सभी विधायकों का विवरण स हासिल है। संजीव शर्मा भी कभी पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री व गाजियाबाद के पूर्व सांसद जनरल वी के सिंह के खासमखास रह चुके हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से पहली बार महानगर अध्यक्ष के पद तक पहुंचे थे। लेकिन तत्कालीन सांसद और विधायकों के बीच बड़ती दूरियों के चलते उन्होंने विधायकों का साथ दिया, जिससे न केवल दूसरी बार महानगर अध्यक्ष बने, बल्कि विधायक चुनाव का टिकट हासिल करने में भी सफल रहे। गाजियाबाद में भाजपा का टिकट मिलने को ही जीत की गारंटी समझी जाती है।
सवाल है कि पहले लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान गाजियाबाद के सांसद और केंद्रीय मंत्री रहे जनरल वी के सिंह, पूर्व थल सेनाध्यक्ष को जिस तरह से निपटया गया, उससे राजपूत समाज में भारी रोष है। लेकिन यू पी विस उपचुनाव में गाजियाबाद सदर सीट से उनकी पुत्री मुगालिनी सिंह को टिकट नहीं दिए जाने से क्षत्रिय समाज अब जनपद की राजनीति में पूरी तरह से खुद को उर्ध्वक्षित महसूस कर रहा है।
वहीं, चर्चा है कि इससे पूर्व गाजियाबाद नगर निगम चुनाव 2022 में टिकट बंटवारे पर सवाल उठना लाजमी है। बताया जा रहा है कि यहां लिए जा रहे हर फैसले का मकसद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कमजोर करना है, जो आरएसएस को साधक भाजपा का काफी बड़ा चेहरा बन चुके हैं और 2029 में पीएम पद के प्रबल दावेदार हैं, जिससे अमित शाह की आंखों में वो खटक रहे हैं। उन्हीं के इशारे पर उपमुख्यमंत्री केपी मौर्य योगी की राह में जबतब रोड़ा अटकते रहते हैं। खासकर उस गाजियाबाद जनपद में जिसे भाजपा का किला करार दिया जाता है।
चर्चा है कि पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022, फिर गाजियाबाद नगर निगम चुनाव 2022, उसके बाद लोकसभा चुनाव 2024, और अब विधानसभा उपचुनाव 2024 में जिस तरह से टिकट बांटे गए हैं, उससे पार्टी कार्यकर्ताओं के दिलोंदिमाग में यह सवाल कौंध रहा है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कमजोर करने के चक्कर में केंद्रीय भाजपा ने तत्व कहां तक गिराया! सभी हिंदुओं को

संगठनात्मक रोष बढ़ा और जनअसंतोष हावी हुआ, उसे संतुलित करने का प्रयास भाजपा केंद्रीय नेतृत्व क्यों नहीं कर रहा है, यह समझ से परे है।
स्थानीय भाजपा नेता देवी चुबान में बताते हैं कि औद्योगिक नगरी गाजियाबाद की सियासत 'थैलीशाहों' के कब्जे में चलने से पार्टी के वोटर्स के अर्थव्यवस्था में परेशान हैं, क्योंकि उन्हें उनका भविष्य अब अंधकारमय नजर आ रहा है। बताया जाता है कि गाजियाबाद में भाजपा के फैसले से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाराज नहीं हो, इसके डैमज मंत्री स्वतंत्र प्रभार को वोटर्स के वैश्यों और ब्राह्मणों पर विशेष कृपा बरसायी जा रही है, जिससे क्षत्रिय समाज खुद को उर्ध्वक्षित महसूस कर रहा है।
यही नहीं, दलित और ओबीसी वर्ग के नेताओं में भी इससे अंतरूनी रोष है, लेकिन महानगर क्षेत्र होने, वैश्य-ब्राह्मण वर्ग के संस्थाबल में भारी होने से वो लाचार हो जाते हैं। यू तो अल्पसंख्यक और दलित वर्गों की आवादी भी यहां ठीकठाक है, लेकिन प्रतिनिधित्व नदारद। भले ही एक बार दलित को राष्ट्रपति बनाया गया और केंद्र व राज्य में मंत्रिपद दिया गया। जबकि दलित सिर्फ पार्षद बनकर संतुष्ट हैं। क्योंकि वो मायावती के चोटवैक समझे जाते हैं। शायद इसलिए उन्हें गाजियाबाद से सांसद व विधायक बनाने में पार्टी कोई दिल्चस्पी नहीं लेती।
वहीं, ओबीसी उपराष्ट्रपति, ओबीसी पीएम और केंद्र व राज्य में दर्जनों ओबीसी मंत्रियों के होने के चलते गाजियाबाद जैसे महानगर में पार्टी उन्हें सांसद या विधायक के पदों पर ज्यादा तरजीह नहीं देना चाहती, क्योंकि मूल रूप से ओबीसी वोटर्स सपा प्रमुख अखिलेश यादव के समर्थक समझे जाते हैं। वहीं, अल्पसंख्यक कांफ्रेंस समर्थक है, इसलिए भाजपा उन्हें घास नहीं डालती। बावजूद इसके, एक ओबीसी नेता नरेंद्र कश्यप को कबीना मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया और केंद्र व राज्य में मंत्रिपद दिया गया। जबकि दलित सिर्फ पार्षद बनकर संतुष्ट हैं। क्योंकि वो मायावती के चोटवैक समझे जाते हैं। शायद इसलिए उन्हें गाजियाबाद से सांसद व विधायक बनाने में पार्टी कोई दिल्चस्पी नहीं लेती।
वहीं, ओबीसी उपराष्ट्रपति, ओबीसी पीएम और केंद्र व राज्य में दर्जनों ओबीसी मंत्रियों के होने के चलते गाजियाबाद जैसे महानगर में पार्टी उन्हें सांसद या विधायक के पदों पर ज्यादा तरजीह नहीं देना चाहती, क्योंकि मूल रूप से ओबीसी वोटर्स सपा प्रमुख अखिलेश यादव के समर्थक समझे जाते हैं। वहीं, अल्पसंख्यक कांफ्रेंस समर्थक है, इसलिए भाजपा उन्हें घास नहीं डालती। बावजूद इसके, एक ओबीसी नेता नरेंद्र कश्यप को कबीना मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया और केंद्र व राज्य में मंत्रिपद दिया गया। जबकि दलित सिर्फ पार्षद बनकर संतुष्ट हैं। क्योंकि वो मायावती के चोटवैक समझे जाते हैं। शायद इसलिए उन्हें गाजियाबाद से सांसद व विधायक बनाने में पार्टी कोई दिल्चस्पी नहीं लेती।
वहीं, ओबीसी उपराष्ट्रपति, ओबीसी पीएम और केंद्र व राज्य में दर्जनों ओबीसी मंत्रियों के होने के चलते गाजियाबाद जैसे महानगर में पार्टी उन्हें सांसद या विधायक के पदों पर ज्यादा तरजीह नहीं देना चाहती, क्योंकि मूल रूप से ओबीसी वोटर्स सपा प्रमुख अखिलेश यादव के समर्थक समझे जाते हैं। वहीं, अल्पसंख्यक कांफ्रेंस समर्थक है, इसलिए भाजपा उन्हें घास नहीं डालती। बावजूद इसके, एक ओबीसी नेता नरेंद्र कश्यप को कबीना मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया और केंद्र व राज्य में मंत्रिपद दिया गया। जबकि दलित सिर्फ पार्षद बनकर संतुष्ट हैं। क्योंकि वो मायावती के चोटवैक समझे जाते हैं। शायद इसलिए उन्हें गाजियाबाद से सांसद व विधायक बनाने में पार्टी कोई दिल्चस्पी नहीं लेती।
वहीं, ओबीसी उपराष्ट्रपति, ओबीसी पीएम और केंद्र व राज्य में दर्जनों ओबीसी मंत्रियों के होने के चलते गाजियाबाद जैसे महानगर में पार्टी उन्हें सांसद या विधायक के पदों पर ज्यादा तरजीह नहीं देना चाहती, क्योंकि मूल रूप से ओबीसी वोटर्स सपा प्रमुख अखिलेश यादव के समर्थक समझे जाते हैं। वहीं, अल्पसंख्यक कांफ्रेंस समर्थक है, इसलिए भाजपा उन्हें घास नहीं डालती। बावजूद इसके, एक ओबीसी नेता नरेंद्र कश्यप को कबीना मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया और केंद्र व राज्य में मंत्रिपद दिया गया। जबकि दलित सिर्फ पार्षद बनकर संतुष्ट हैं। क्योंकि वो मायावती के चोटवैक समझे जाते हैं। शायद इसलिए उन्हें गाजियाबाद से सांसद व विधायक बनाने में पार्टी कोई दिल्चस्पी नहीं लेती।
वहीं, ओबीसी उपराष्ट्रपति, ओबीसी पीएम और केंद्र व राज्य में दर्जनों ओबीसी मंत्रियों के होने के चलते गाजियाबाद जैसे महानगर में पार्टी उन्हें सांसद या विधायक के पदों पर ज्यादा तरजीह नहीं देना चाहती, क्योंकि मूल रूप से ओबीसी वोटर्स सपा प्रमुख अखिलेश यादव के समर्थक समझे जाते हैं। वहीं, अल्पसंख्यक कांफ्रेंस समर्थक है, इसलिए भाजपा उन्हें घास नहीं डालती। बावजूद इसके, एक ओबीसी नेता नरेंद्र कश्यप को कबीना मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया और केंद्र व राज्य में मंत्रिपद दिया गया। जबकि दलित सिर्फ पार्षद बनकर संतुष्ट हैं। क्योंकि वो मायावती के चोटवैक समझे जाते हैं। शायद इसलिए उन्हें गाजियाबाद से सांसद व विधायक बनाने में पार्टी कोई दिल्चस्पी नहीं लेती।
वहीं, ओबीसी उपराष्ट्रपति, ओबीसी पीएम और केंद्र व राज्य में दर्जनों ओबीसी मंत्रियों के होने के चलते गाजियाबाद जैसे महानगर में पार्टी उन्हें सांसद या विधायक के पदों पर ज्यादा तरजीह नहीं देना चाहती, क्योंकि मूल रूप से ओबीसी वोटर्स सपा प्रमुख अखिलेश यादव के समर्थक समझे जाते हैं। वहीं, अल्पसंख्यक कांफ्रेंस समर्थक है, इसलिए भाजपा उन्हें घास नहीं डालती। बावजूद इसके, एक ओबीसी नेता नरेंद्र कश्यप को कबीना मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया और केंद्र व राज्य में मंत्रिपद दिया गया। जबकि दलित सिर्फ पार्षद बनकर संतुष्ट हैं। क्योंकि वो मायावती के चोटवैक समझे जाते हैं। शायद इसलिए उन्हें गाजियाबाद से सांसद व विधायक बनाने में पार्टी कोई दिल्चस्पी नहीं लेती।
वहीं, ओबीसी उपराष्ट्रपति, ओबीसी पीएम और केंद्र व राज्य में दर्जनों ओबीसी मंत्रियों के होने के चलते गाजियाबाद जैसे महानगर में पार्टी उन्हें सांसद या विधायक के पदों पर ज्यादा तरजीह नहीं देना चाहती, क्योंकि मूल रूप से ओबीसी वोटर्स सपा प्रमुख अखिलेश यादव के समर्थक समझे जाते हैं। वहीं, अल्पसंख्यक कांफ्रेंस समर्थक है, इसलिए भाजपा उन्हें घास नहीं डालती। बावजूद इसके, एक ओबीसी नेता नरेंद्र कश्यप को कबीना मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया और केंद्र व राज्य में मंत्रिपद दिया गया। जबकि दलित सिर्फ पार्षद बनकर संतुष्ट हैं। क्योंकि वो मायावती के चोटवैक समझे जाते हैं। शायद इसलिए उन्हें गाजियाबाद से सांसद व विधायक बनाने में पार्टी कोई दिल्चस्पी नहीं लेती।
वहीं, ओबीसी उपराष्ट्रपति, ओबीसी पीएम और केंद्र व राज्य में दर्जनों ओबीसी मंत्रियों के होने के चलते गाजियाबाद जैसे महानगर में पार्टी उन्हें सांसद या विधायक के पदों पर ज्यादा तरजीह नहीं देना चाहती, क्योंकि मूल रूप से ओबीसी वोटर्स सपा प्रमुख अखिलेश यादव के समर्थक समझे जाते हैं। वहीं, अल्पसंख्यक कांफ्रेंस समर्थक है, इसलिए भाजपा उन्हें घास नहीं डालती। बावजूद इसके, एक ओबीसी नेता नरेंद्र कश्यप को कबीना मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया और केंद्र व राज्य में मंत्रिपद दिया गया। जबकि दलित सिर्फ पार्षद बनकर संतुष्ट हैं। क्योंकि वो मायावती के चोटवैक समझे जाते हैं। शायद इसलिए उन्हें गाजियाबाद से सांसद व विधायक बनाने में पार्टी कोई दिल्चस्पी नहीं लेती।
वहीं, ओबीसी उपराष्ट्रपति, ओबीसी पीएम और केंद्र व राज्य में दर्जनों ओबीसी मंत्रियों के होने के चलते गाजियाबाद जैसे महानगर में पार्टी उन्हें सांसद या विधायक के पदों पर ज्यादा तरजीह नहीं देना चाहती, क्योंकि मूल रूप से ओबीसी वोटर्स सपा प्रमुख अखिलेश यादव के समर्थक समझे जाते हैं। वहीं, अल्पसंख्यक कांफ्रेंस समर्थक है, इसलिए भाजपा उन्हें घास नहीं डालती। बावजूद इसके, एक ओबीसी नेता नरेंद्र कश्यप को कबीना मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया और केंद्र व राज्य में मंत्रिपद दिया गया। जबकि दलित सिर्फ पार्षद बनकर संतुष्ट हैं। क्योंकि वो मायावती के चोटवैक समझे जाते हैं। शायद इसलिए उन्हें गाजियाबाद से सांसद व विधायक बनाने में पार्टी कोई दिल्चस्पी नहीं लेती।
वहीं, ओबीसी उपराष्ट्रपति, ओबीसी पीएम और केंद्र व राज्य में दर्जनों ओबीसी मंत्रियों के होने के चलते गाजियाबाद जैसे महानगर में पार्टी उन्हें सांसद या विधायक के पदों पर ज्यादा तरजीह नहीं देना चाहती, क्योंकि मूल रूप से ओबीसी वोटर्स सपा प्रमुख अखिलेश यादव के समर्थक समझे जाते हैं। वहीं, अल्पसंख्यक कांफ्रेंस समर्थक है, इसलिए भाजपा उन्हें घास नहीं डालती। बावजूद इसके, एक ओबीसी नेता नरेंद्र कश्यप को कबीना मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया और केंद्र व राज्य में मंत्रिपद दिया गया। जबकि दलित सिर्फ पार्षद बनकर संतुष्ट हैं। क्योंकि वो मायावती के चोटवैक समझे जाते हैं। शायद इसलिए उन्हें गाजियाबाद से सांसद व विधायक बनाने में पार्टी कोई दिल्चस्पी नहीं लेती।
वहीं, ओबीसी उपराष्ट्रपति, ओबीसी पीएम और केंद्र व राज्य में दर्जनों ओबीसी मंत्रियों के होने के चलते गाजियाबाद जैसे महानगर में पार्टी उन्हें सांसद या विधायक के पदों पर ज्यादा तरजीह नहीं देना चाहती, क्योंकि मूल रूप से ओबीसी वोटर्स सपा प्रमुख अखिलेश यादव के समर्थक समझे जाते हैं। वहीं, अल्पसंख्यक कांफ्रेंस समर्थक है, इसलिए भाजपा उन्हें घास नहीं डालती। बावजूद इसके, एक ओबीसी नेता नरेंद्र कश्यप को कबीना मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया और केंद्र व राज्य में मंत्रिपद दिया गया। जबकि दलित सिर्फ पार्षद बनकर संतुष्ट हैं। क्योंकि वो मायावती के चोटवैक समझे जाते हैं। शायद इसलिए उन्हें गाजियाबाद से सांसद व विधायक बनाने में पार्टी कोई दिल्चस्पी नहीं लेती।
वहीं, ओबीसी उपराष्ट्रपति, ओबीसी पीएम और केंद्र व राज्य में दर्जनों ओबीसी मंत्रियों के होने के चलते गाजियाबाद जैसे महानगर में पार्टी उन्हें सांसद या विधायक के पदों पर ज्यादा तरजीह नहीं देना चाहती, क्योंकि मूल रूप से ओबीसी वोटर्स सपा प्रमुख अखिलेश यादव के समर्थक समझे जाते हैं। वहीं, अल्पसंख्यक कांफ्रेंस समर्थक है, इसलिए भाजपा उन्हें घास नहीं डालती। बावजूद इसके, एक ओबीसी नेता नरेंद्र कश्यप को कबीना मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया और केंद्र व राज्य में मंत्रिपद दिया गया। जबकि दलित सिर्फ पार्षद बनकर संतुष्ट हैं। क्योंकि वो मायावती के चोटवैक समझे जाते हैं। शायद इसलिए उन्हें गाजियाबाद से सांसद व विधायक बनाने में पार्टी कोई दिल्चस्पी नहीं लेती।
वहीं, ओबीसी उपराष्ट्रपति, ओबीसी पीएम और केंद्र व राज्य में दर्जनों ओबीसी मंत्रियों के होने के चलते गाजियाबाद जैसे महानगर में पार्टी उन्हें सांसद या विधायक के पदों पर ज्यादा तरजीह नहीं देना चाहती, क्योंकि मूल रूप से ओबीसी वोटर्स सपा प्रमुख अखिलेश यादव के समर्थक समझे जाते हैं। वहीं, अल्पसंख्यक कांफ्रेंस समर्थक है, इसलिए भाजपा उन्हें घास नहीं डालती। बावजूद इसके, एक ओबीसी नेता नरेंद्र कश्यप को कबीना मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया और केंद्र व राज्य में मंत्रिपद दिया गया। जबकि दलित सिर्फ पार्षद बनकर संतुष्ट हैं। क्योंकि वो मायावती के चोटवैक समझे जाते हैं। शायद इसलिए उन्हें गाजियाबाद से सांसद व विधायक बनाने में पार्टी कोई दिल्चस्पी नहीं लेती।
वहीं, ओबीसी उपराष्ट्रपति, ओबीसी पीएम और केंद्र व राज्य में दर्जनों ओबीसी मंत्रियों के होने के चलते गाजियाबाद जैसे महानगर में पार्टी उन्हें सांसद या विधायक के पदों पर ज्यादा तरजीह नहीं देना चाहती, क्योंकि मूल रूप से ओबीसी वोटर्स सपा प्रमुख अखिलेश यादव के समर्थक समझे जाते हैं। वहीं, अल्पसंख्यक कांफ्रेंस समर्थक है, इसलिए भाजपा उन्हें घास नहीं डालती। बावजूद इसके, एक ओबीसी नेता नरेंद्र कश्यप को कबीना मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया और केंद्र व राज्य में मंत्रिपद दिया गया। जबकि दलित सिर्फ पार्षद बनकर संतुष्ट हैं। क्योंकि वो मायावती के चोटवैक समझे जाते हैं। शायद इसलिए उन्हें गाजियाबाद से सांसद व विधायक बनाने में पार्टी कोई दिल्चस्पी नहीं लेती।
वहीं, ओबीसी उपराष्ट्रपति, ओबीसी पीएम और केंद्र व राज्य में दर्जनों ओबीसी मंत्रियों के होने के चलते गाजियाबाद जैसे महानगर में पार्टी उन्हें सांसद या विधायक के पदों पर ज्यादा तरजीह नहीं देना चाहती, क्योंकि मूल रूप से ओबीसी वोटर्स सपा प्रमुख अखिलेश यादव के समर्थक समझे जाते हैं। वहीं, अल्पसंख्यक कांफ्रेंस समर्थक है, इसलिए भाजपा उन्हें घास नहीं डालती। बावजूद इसके, एक ओबीसी नेता नरेंद्र कश्यप को कबीना मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया और केंद्र व राज्य में मंत्रिपद दिया गया। जबकि दलित सिर्फ पार्षद बनकर संतुष्ट हैं। क्योंकि वो मायावती के चोटवैक समझे जाते हैं। शायद इसलिए उन्हें गाजियाबाद से सांसद व विधायक बनाने में पार्टी कोई दिल्चस्पी नहीं लेती।
वहीं, ओबीसी उपराष्ट्रपति, ओबीसी पीएम और केंद्र व राज्य में दर्जनों ओबीसी मंत्रियों के होने के चलते गाजियाबाद जैसे महानगर में पार्टी उन्हें सांसद या विधायक के पदों पर ज्यादा तरजीह नहीं देना चाहती, क्योंकि मूल रूप से ओबीसी वोटर्स सपा प्रमुख अखिलेश यादव के समर्थक समझे जाते हैं। वहीं, अल्पसंख्यक कांफ्रेंस समर्थक है, इसलिए भाजपा उन्हें घास नहीं डालती। बावजूद इसके, एक ओबीसी नेता नरेंद्र कश्यप को कबीना मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया और केंद्र व राज्य में मंत्रिपद दिया गया। जबकि दलित सिर्फ पार्षद बनकर संतुष्ट हैं। क्योंकि वो मायावती के चोटवैक समझे जाते हैं। शायद इसलिए उन्हें गाजियाबाद से सांसद व विधायक बनाने में पार्टी कोई दिल्चस्पी नहीं लेती।
वहीं, ओबीसी उपराष्ट्रपति, ओबीसी पीएम और केंद्र व राज्य में दर्जनों ओबीसी मंत्रियों के होने के चलते गाजियाबाद जैसे महानगर में पार्टी उन्हें सांसद या विधायक के पदों पर ज्यादा तरजीह नहीं देना चाहती, क्योंकि मूल रूप से ओबीसी वोटर्स सपा प्रमुख अखिलेश यादव के समर्थक समझे जाते हैं। वहीं, अल्पसंख्यक कांफ्रेंस समर्थक है, इसलिए भाजपा उन्हें घास नहीं डालती। बावजूद इसके, एक ओबीसी नेता नरेंद्र कश्यप को कबीना मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया और केंद्र व राज्य में मंत्रिपद दिया गया। जबकि दलित सिर्फ पार्षद बनकर संतुष्ट हैं। क्योंकि वो मायावती के चोटवैक समझे जाते हैं। शायद इसलिए उन्हें गाजियाबाद से सांसद व विधायक बनाने में पार्टी कोई दिल्चस्पी नहीं लेती।
वहीं, ओबीसी उपराष्ट्रपति, ओबीसी पीएम और केंद्र व राज्य में दर्जनों ओबीसी मंत्रियों के होने के चलते गाजियाबाद जैसे महानगर में पार्टी उन्हें सांसद या विधायक के पदों पर ज्यादा तरजीह नहीं देना चाहती, क्योंकि मूल रूप से ओबीसी वोटर्स सपा प्रमुख अखिलेश यादव के समर्थक समझे जाते हैं। वहीं, अल्पसंख्यक कांफ्रेंस समर्थक है, इसलिए भाजपा उन्हें घास नहीं डालती। बावजूद इसके, एक ओबीसी नेता नरेंद्र कश्यप को कबीना मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया और केंद्र व राज्य में मंत्रिपद दिया गया। जबकि दलित सिर्फ पार्षद बनकर संतुष्ट हैं। क्योंकि वो मायावती के चोटवैक समझे जा

- सौजन्य -

ईवी ड्राइव द फ्यूचर



कंपनी दिवाली में अपने डिलीवरी पार्टनर्स को बांट रही सोने-चांदी के सिक्के

परिवहन विशेष न्यूज

जिप इलेक्ट्रिक ने अपने डिलीवरी पार्टनर्स की दिवाली को खास बनाने के लिए 'जिप दिवाली बोनान्जा: टॉप 30 राइडर्स पैन-इंडिया टू गेट गोल्ड, सिल्वर कॉइन्स' पेश किया है, जिसमें टॉप परफॉर्मर को सोने और चांदी के सिक्के मिलेंगे। वहीं, जिप इलेक्ट्रिक के सबसे पुराने 5 डिलीवरी पार्टनर्स को 15 लाख रुपये के ईसांप भी मिलेंगे, जो कि उनकी वित्तीय सुरक्षा बेहतर करने में मददगार साबित होंगे। कंपनी अपने मौजूदा और भूतपूर्व पायलट्स के लिए दिवाली के दिन यानि 31 अक्टूबर को दोगुनी कमाई करने का खास मौका लेकर आ

रही है।

जिप इलेक्ट्रिक का यह कैपेन त्योहारों को देखते हुए इनाम देने की एक पहल है, जिसमें दिवाली मनाते हुए गिग वर्कर्स की आमदनी बढ़ाई जाएगी और उन्हें लंबे वक्त तक फायदे मिलेंगे। यह उनकी कड़ी मेहनत और कंपनी में उनके योगदानों का सम्मान होगा। इस कैपेन का मुख्य आकर्षण है सबसे ज्यादा समय से काम कर रहे जिप पायलट्स को सम्मानित करने के लिए जिप इलेक्ट्रिक की प्रतिबद्धता। कंपनी पांच सम्पित पायलट्स के लिए 15 लाख रुपये के एम्प्लॉयी स्टॉक ऑनरशिप प्लान (ईसांप) पेश कर रही है।

फेस्टिवल सीजन क्विक-कॉमर्स, ई-कॉमर्स और फूड डिलीवरीज के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें जुझारू गिग वर्कफोर्स की जरूरत होती है और हर डिलीवरी पार्टनर कड़ी मेहनत करता है। उनकी कोशिशों के बदले इनाम देने की खास पहल के तहत जिप इलेक्ट्रिक टॉप 30 जिप पायलट्स को उनके प्रदर्शन के आधार पर सोने और चांदी के सिक्के देगी। इसके अलावा अपने गिग वर्कफोर्स को भागीदारी बढ़ाने के लिये जिप 31 अक्टूबर को दोगुनी कमाई करने का मौका दे रही है। इस खास दिन मौजूदा और भूतपूर्व पायलट्स प्लान (ईसांप) पेश कर रही है।

जिप इलेक्ट्रिक ने अपने पायलट्स के लिए रेंट-टू-ओन फॉर्मेट में जिप इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑनरशिप प्लान भी पेश किया है। इसके द्वारा वे बिना अतिरिक्त खर्च के उन स्कूटरों के मालिक बन सकते हैं, जिन्हें वे चलाते हैं। जिप इलेक्ट्रिक के को-फाउंडर और सीईओ आकाश गुप्ता का कहना है कि डिलीवरी एगिजक्यूटिव्स को हम जिप पायलट्स कहते हैं और वही हमारे परिचालन की रीढ़ हैं। इस दिवाली हम उन्हें इस तरह से कुछ लौटाना चाहते हैं कि असलियत में बदलाव हो सके। कंपनी के पास मौजूदा समय में 22,000 से ज्यादा जिप डिलीवरी पायलट्स हैं।



महा-ईवी मिशन के तहत प्रस्तावों के लिए हितधारकों की बैठक के ज़रिए भारत के स्मार्ट परिवहन अनुसंधान को चलाने के लिए विशेषज्ञ एक साथ आए

परिवहन विशेष न्यूज

देश के ई-मोबिलिटी इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों पर चर्चा करने हेतु मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई-इम्पैक्ट एरियाज (एमएएचए) इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) मिशन के तहत हितधारकों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के विभिन्न पहलुओं पर काम करने वाले शोधकर्ता, उद्योग जगत के नेता और विशेषज्ञ एक साथ आए।

“हमने राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप सतत गतिशीलता के लिए भारत के विचार का समर्थन करने हेतु इस मिशन को शुरू किया है। हमारे ऑटोमोबाइल क्षेत्र के भीतर ई-मोबिलिटी के महत्व को ओवरस्ट्रेटेड नहीं किया जा सकता है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय के सुंद ने महा-ईवी पर कॉल के जवाब में आए प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए विज्ञान भवन में आयोजित बैठक में कहा, “यह मिशन हितधारकों के बीच नवाचार और सहयोग को उत्प्रेरित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत ईवी प्रौद्योगिकी में मजबूत विशेषज्ञता का निर्माण करे।” एमएएचए-ईवी नव संचालित अनुसंधान राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन की पहली कॉल में से एक है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव और एएनआरएफ के सीईओ प्रोफेसर अभय करंदीकर ने महा-ईवी मिशन के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों पर प्रकाश डाला। प्रोफेसर करंदीकर ने कहा, रहस्यमय एएनआरएफ के ज़रिए महत्वपूर्ण निवेश शुरू किया है, तथा मिशन की रणनीति का मार्गदर्शन करने के लिए एक उच्च स्तरीय गवर्निंग बोर्ड की स्थापना की



है। महा-ईवी मिशन का मकसद ईवी बैटरी प्रौद्योगिकी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और चार्जिंग से जुड़े बुनियादी ढांचे में प्रगति को बढ़ावा देना है। हमने संस्थानों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं और उद्योगों में अंतर्विषयक अनुसंधान और विकास को सक्षम करने के लिए कंसोर्टिया मोड में प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं।

महा-ईवी मिशन पर एएनआरएफ की पहली कॉल का मकसद ईवी बैटरी प्रौद्योगिकी में भारत की विशेषज्ञता को बढ़ावा देना, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनों और ड्राइव में आर एंड डी को मजबूत करना तथा चार्जिंग बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। इसे

राष्ट्रीय प्राथमिकता के क्षेत्र में तेजी से ट्रांसलेशनल अनुसंधान, नवाचार और तकनीकी सफलताओं को ट्रैक करने और वैश्विक प्रभाव लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

हितधारकों की बैठक में एकत्र हुए प्रतिभागियों के उत्साह ने टिकाऊ परिवहन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास के विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाया।

इस बैठक ने एक सहभागी मंच के रूप में कार्य किया, जिसमें 300 से अधिक प्रतिभागी अकादमिक, सरकारी एजेंसियों और उद्योग जगत का प्रतिनिधित्व

करते हुए व्यक्तिगत रूप से और ऑनलाइन माध्यम से शामिल हुए। उन्होंने महा-ईवी मिशन के तहत वर्तमान कॉल के लिए अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तैयारी के लिए वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की।

एएनआरएफ में ईवी मिशन के कार्यक्रम समन्वयक डॉ. शशि भूषण पांडे ने जोर देकर कहा कि इस तरह की साझेदारी को बढ़ावा देने से भारत के ईवी परिदृश्य में बेहतर तरक्की होगी।

इस कार्यक्रम के दौरान, डीएसटी के सचिव प्रोफेसर अभय करंदीकर ने उष्णकटिबंधीय ईवी

बैटरी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन और ड्राइव और ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर तीन विषयगत आर एंड डी रोडमैप का अनावरण किया, जिन्हें डीएसटी द्वारा तैयार किया गया था। इसके साथ ही इन रिपोर्टों की सॉफ्ट कॉपी भी डीएसटी वेबसाइट पर अपलोड की गई थी।

इससे पहले डीएसटी ने ई-मोबिलिटी पर एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया था, जिसके बाद पीएसए कार्यालय द्वारा ई-मोबिलिटी आर एंड डी रोडमैप जारी किया गया था। तीन विषयगत आर एंड डी रोडमैप के साथ इन दो रिपोर्टों के परिणाम से मिशन

फॉर एडवांसमेंट इन हाई-इम्पैक्ट एरियाज (एमएएचए): ईवी-मिशन का निर्माण हुआ, जिसे एएनआरएफ द्वारा चलाया जाएगा।

इस विचार-मंथन बैठक में जलवायु, ऊर्जा और सतत परिवहन (सीईएसटी) प्रमुख डॉ. अनीता गुप्ता और अन्य वरिष्ठ डीएसटी और एएनआरएफ अधिकारियों ने भी भाग लिया।

महा-ईवी पहल, वैश्विक ईवी क्षेत्र में भारत की स्थिति को ऊंचा करने और प्रतिस्पर्धी, टिकाऊ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रौद्योगिकियों के विकास में योगदान करने की आकांक्षा रखती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे में बाधाएं

परिवहन विशेष न्यूज

जैसे-जैसे इलेक्ट्रिक वाहन दुनिया भर में लोकप्रिय होते जा रहे हैं, व्यापक, सुलभ ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता महत्वपूर्ण हो गई है। जबकि शहरी क्षेत्रों में चार्जिंग स्टेशनों में महत्वपूर्ण निवेश देखा गया है, ग्रामीण क्षेत्र अक्सर पीछे रह जाते हैं। यह विसंगति ग्रामीण क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों को बड़े पैमाने पर अपनाने में एक महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न करती है, जहाँ लंबी दूरी, विरल आबादी और अद्वितीय भौगोलिक चुनौतियाँ एक कुशल ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में अलग-अलग बाधाएँ पेश करती हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विकास में प्रमुख बाधाओं का पता लगाएँ और इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के भविष्य के लिए ईवी चार्जिंग क्यों महत्वपूर्ण है।

विरल जनसंख्या घनत्व और इलेक्ट्रिक वाहनों की कम मांग

ग्रामीण क्षेत्रों में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में सबसे बड़ी बाधा जनसंख्या घनत्व का कम होना है। ग्रामीण क्षेत्रों में आम तौर पर शहरी क्षेत्रों की तुलना में कम लोग रहते हैं, जिसके परिणामस्वरूप इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग कम होती है। इससे कंपनियों के लिए ईवी चार्जिंग स्टेशनों में निवेश करना आर्थिक रूप से कम व्यवहार्य हो जाता है, क्योंकि उन्हें निवेश पर तत्काल लाभ नहीं मिल सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों पर कम इलेक्ट्रिक वाहनों के होने से चार्जिंग स्टेशन बनाने और बनाए रखने का प्रोत्साहन कम हो जाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग भी चुनौतियों का सामना कर रही है, क्योंकि ईवी के लाभों के बारे में लोगों में जागरूकता सीमित है। इन क्षेत्रों में लोग ईवी अपनाने के रुझानों से कम परिचित हो सकते हैं, जिससे पारंपरिक गैसोलिन वाहनों से संक्रमण धीमा हो सकता है। नतीजतन, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को प्राथमिकता नहीं दी जाती है, जिससे एक ऐसा चक्र बनता है जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने से हतोत्साहित करती है।

ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विकास की उच्च लागत

ईवी चार्जिंग नेटवर्क बनाने के लिए बुनियादी ढांचे में पर्याप्त निवेश की आवश्यकता होती है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहाँ चार्जिंग पॉइंट के बीच की दूरी अधिक होती है। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने, पर्याप्त प्राप्त करने और विश्वसनीय बिजली स्रोतों तक पहुँच सुनिश्चित करने की लागत काफी अधिक हो सकती है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण घरों और राजमार्गों के बीच लंबी दूरी का मतलब है कि चार्जिंग स्टेशनों को और अधिक दूरी पर रखना होगा, जिससे प्रति स्टेशन लागत बढ़ जाती है।

इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों को विश्वसनीय विद्युत ग्रिड से भी जोड़ा जाना चाहिए, जिसके लिए मौजूदा बिजली लाइनों को अपग्रेड

करने या नए ग्रिड कनेक्शन बनाने की आवश्यकता हो सकती है। इससे और भी खर्च बढ़ जाता है, खासकर दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में जहाँ बिजली का बुनियादी ढांचा शहरी क्षेत्रों जितना उन्नत या व्यापक नहीं हो सकता है।

ग्रिड विश्वसनीयता और बिजली उपलब्धता

ग्रामीण क्षेत्रों में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बिजली की विश्वसनीयता और उपलब्धता है। इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों को स्थिर, उच्च क्षमता वाले पावर ग्रिड तक पहुँच की आवश्यकता होती है, और कई ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर या कम विश्वसनीय विद्युत ग्रिड होते हैं। दूरदराज के क्षेत्रों में बिजली की कटौती या बिजली आपूर्ति में उतार-चढ़ाव अधिक आम है, जो ईवी चार्जिंग स्टेशनों को प्रभावी ढंग से संचालित करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है।

उदाहरण के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों में लंबी दूरी की यात्रा के लिए महत्वपूर्ण फास्ट-चार्जिंग स्टेशन, वाहनों को जल्दी से चार्ज करने के लिए बड़ी मात्रा में बिजली की आवश्यकता होती है। ग्रामीण ग्रिड में महत्वपूर्ण उन्नयन के बिना ऐसी उच्च ऊर्जा मांगों को पूरा करने की क्षमता नहीं हो सकती है, जिससे इन क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए फास्ट-चार्जिंग विकल्प प्रदान करना मुश्किल हो जाता है।

भौगोलिक एवं पर्यावरणीय चुनौतियाँ

ग्रामीण क्षेत्रों की भौगोलिक विशेषताएँ ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में अतिरिक्त बाधाएँ उत्पन्न करती हैं। कई ग्रामीण क्षेत्रों में पहाड़, रेगिस्तान या जंगल जैसे कठिन भूभाग हैं, जो ईवी चार्जिंग स्टेशनों को स्थापित करना और उनका रखरखाव करना ताकिक रूप से चुनौतीपूर्ण बना सकते हैं। कुछ मामलों में, निकटतम बिजली की लाइनें संभावित चार्जिंग स्टेशन स्थानों से मीलों दूर हो सकती हैं, जिससे साइट पर बिजली लाने के लिए व्यापक निर्माण की आवश्यकता होती है।

चरम मौसम जैसे पर्यावरणीय परिस्थितियों भी ग्रामीण क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की व्यवहार्यता को प्रभावित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, बर्फबारी, बाढ़ या तेज हवाओं से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली लाइनों और सड़कों में अधिक बार व्यवधान आ सकता है, जिससे ऐसी परिस्थितियों में ईवी चार्जिंग स्टेशन कम विश्वसनीय हो जाते हैं। ये भौगोलिक और पर्यावरणीय कारक ग्रामीण ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विकास में जटिलता की एक और परत जोड़ते हैं।

चार्जिंग पॉइंट्स के बीच रेंज एंजायटी और लंबी दूरी

रेंज एंजायटी - यह डर कि इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन तक पहुँचने से पहले ही बैटरी पावर खत्म हो जाएगी - ग्रामीण क्षेत्रों में ड्राइवर्स के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। दूरदराज के क्षेत्रों में कम ईवी चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध होने के कारण, इलेक्ट्रिक वाहन मालिक लंबी दूरी तक ड्राइव करने से हिचकिचा सकते हैं, उन्हें डर है कि जरूरत पड़ने



पर उन्हें चार्जिंग पॉइंट नहीं मिल पाएगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में गंतव्यों के बीच लंबी दूरी इस समस्या को और बढ़ा देती है। शहरी वातावरण के विपरीत, जहाँ इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन अधिक केंद्रित हैं, ग्रामीण चालकों को चार्जिंग स्टेशनों के बीच सैकड़ों मील की यात्रा करनी पड़ सकती है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में एक मनोवैज्ञानिक बाधा पैदा करता है, क्योंकि ईवी चार्जिंग की सुविधा और पहुँच को अपर्याप्त माना जाता है।

नीतिगत समर्थन और प्रोत्साहन का अभाव

सरकारी नीतियाँ और प्रोत्साहन ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इन पहलों पर अक्सर कम ध्यान दिया जाता है। अधिकांश सरकारी कार्यक्रम जो इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने को बढ़ावा देते हैं या चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए सब्सिडी प्रदान करते हैं, वे शहरी केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जहाँ मांग अधिक होती है, और निवेश पर रिटर्न स्पष्ट होता है।

हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर नीतिगत समर्थन का समान स्तर नहीं होता है, जो ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में बाधा डालता है। लक्षित प्रोत्साहन या फंडिंग के बिना, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय और स्थानीय सरकारें इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने में अनिच्छुक हो सकती हैं। नीतिगत ध्यान में यह असमानता इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग उपलब्धता की बात आने पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच बढ़ते अंतर में योगदान करती है।

ओला के बाद अब एक और ईवी कंपनी पर गज, भेजा जा सकता है नोटिस

परिवहन विशेष न्यूज

ग्राहकों की लगातार मिल रही शिकायतों पर ओला को नोटिस भेजकर सवाल पूछे गए हैं। ओला के बाद अब एक और इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी को नोटिस भेजा जा सकता है। यह नोटिस केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण जल्द ही भेज सकता है। ओला के बाद देश की अन्य कंपनियों पर भी नजर रखी जा रही है। इसी निगरानी के चलते जल्द ही एक और ईवी कंपनी को सीसीपीए से नोटिस मिल सकता है। यह कंपनी कौन सी है, इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है।



दीवाली के त्योहार पर परंपराओं के साथ पर्यावरण की भी लें सुध

विजय गर्ग



जैसे-जैसे दिवाली पास आ रही है, उसकी तैयारी तेज होती जा रही है।

पर, उसके साथ ही एक चिंता भी गहराती जा रही है कि इस बार भी प्रदूषण का स्तर कितना बढ़ जाएगा? प्रदूषण के इस फिफ्र को अचानक से फुर्र तो नहीं किया जा सकता है, पर उसे कम करने की ओर समझदारी भरें कदम जरूर बढ़ाए जा सकते हैं। इसके लिए आपको दिवाली मनाने के तरीके और मिजाज दोनों में बदलाव करने होंगे। और इसकी शुरुआत आपको अपने घर से करनी होगी: दीया से जगमग करें घर हम शॉर्टकट में इतना ज्यादा विश्वास करते हैं। कि दीये के भी विकल्प खोज चुके हैं। मोमबत्ती, दीये जैसी दिखनी वाली लाइट अब हमारी दिवाली को रोशन करने लग गई हैं। पर, क्या कभी सोचना कि मोम परसों के तेल के दीये क्यों जलाते थे? छोटे से ये दीये सिर्फ रोशनी नहीं देते हैं बल्कि प्रदूषण, कीट पतंगों को भी भगाते हैं। नैचुरोपैथ डॉ. राजेश मिश्र की मानें तो सरसों के तेल में मैग्नीशियम, ट्राइग्लिसराइड और एलिल आइसोथियोसाइनेट होता है। एलिल कीट-पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दीपक के पास आने पर सफेद कण जमा देखे होंगे, जो तेल के मैग्नीशियम के कारण मुमकिन हो पाता है। विश्वले तत्व भारी होकर जमीन पर आ गिरते हैं, हवा हल्की हो जाती है और हम आसानी से सांस ले पाते हैं। आप मिट्टी के दीयों के साथ ही गाय के गोबर से बने दीयों को भी प्रयोग कर सकते हैं, जिनको जलाने के बाद आप आप पेड़ों में खाद के तौर पर भी प्रयोग कर सकते हैं।

प्राकृतिक चीजों का करें प्रयोग
बिना सजावट दिवाली की कल्पना करना थोड़ा मुश्किल सा है। पर, इको-



फ्रेडली दिवाली मनाने के लिए इस बार अपनी सजावट में प्रकृति के रंगों को ज्यादा से ज्यादा भरने की कोशिश कीजिए। प्लास्टिक के आर्टिफिशियल फूलों और बंदनवार की जगह घर के दरवाजे को ताजे फूलों की लड़ियों और फूल-पत्तियों के बंदनवार से सजाइए। आप घर की सजावट के लिए गुलाब का प्रयोग कर सकती हैं। यह मन को शांत करने के साथ ही तनाव भी दूर करेगा। चमेली सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करती है। इस फूल की खुशबू पूरे माहौल को तनाव मुक्त बना देती है। रंगोली को भी केमिकल वाले रंगों से मुक्त रखने की कोशिश कीजिए। इसके लिए फूलों से लेकर अनाज तक की रंगोली बनाई जा सकती है।

सुगंध को कीजिए शामिल
सुगंध दिवाली के मोके पर हमारे घर के साथ ही साथ हमारे व्यक्तित्व पर भी असर डालेगी। मनोचिकित्सक डॉ. बताती हैं कि खुशबू हमारे दिमाग के उस हिस्से पर असर डालती है, जो याददाश्त और मूड के लिए जिम्मेदार होता है। यह हमारी ऊर्जा में इजाफा कर सकती है। साथ ही साथ सुगंध हमारे तनाव में भी खासी कमी लाती है। यह हमारे डर के भावों को भी खत्म करने में मददगार साबित हो सकती है। कहते हैं

इससे आप स्नायु तंत्र से जुड़ी और अवसाद सरीखी समस्याओं से भी निजात पा पाती हैं। तो यकीनन इस दिवाली खुशबू से अपना और अपने घर नाता जोड़ ही लीजिए। घर को खुशबूदार रखने के लिए डिफ्यूजर की मदद लें।

पकवानों में दें देसी तड़का
त्योहार मतलब खाने खिलाने का दौर। जहां आपके पास ढेरों विकल्प मौजूद हैं। पर, यहां पर परंपरा या यूं कहें देसी तड़का ही फायदे का सौदा होगा। लिहाजा, अपने पकवानों को देसी मसालों के स्वाद से सजाकर ही परोसे। डॉ. किमता की मानें तो हमारे देसी मसाले भी हमारे तनाव को कम

करने का काम करते हैं। जैसे दालचीन, लौंग वगैरह की खुशबू हमारे दिमाग को संतुलित करने का काम करती है। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन में एंटी-इंफ्लामेट्री गुण होते हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। आतिशबाजी से दूरी अच्छी

हर साल दिवाली के पटाखों की धुंध सांस लेने में परेशानी पैदा कर जाती है। चारों जमा स्मॉग भी हमारी आफत को बढ़ा जाता है। तो क्यों न इस बार दिवाली बिना पटाखे वाली रखी जाए। चलाना ही है तो स्पाकलर सरीखे पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को चुनें। कंदील, स्काई लालटेन सरीखे विकल्पों को चुनकर भी दिवाली का

जश्न खुबसूरती के साथ मना सकते हैं। तोहफों में तोहफों का आदान-प्रदान तो बनता ही है। पर, उसके साथ आया अनचाहा कचरा यानी उसको आकर्षक बनाने के लिए लपेटे गई पैकिंग हमारी प्रकृति के लिए बड़ी मुसीबत बन जाती है। यह मुसीबत और न बढ़ने पाए इसके लिए उपहार देने के लिए कपड़े या जूट के बैग का आप प्रयोग कर सकती हैं। उपहार भी पर्यावरण फ्रेंडली रखे जा सकते हैं।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक स्तंभकार स्ट्रीट कोर चंद एमएचआर मलतो पंजाब

लगभग 23 'मार्केट रिसर्च', बर्लिन के ताजा आंकड़ों के अनुसार, हमारी वर्तमान तैयारियां पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्यों से बहुत पीछे हैं। यही स्थिति रही, तो पृथ्वी का औसत तापमान अगले चार साल और नौ महीने में 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। वहीं 2.0 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि को पार करने में साल का समय शेष है। यह ध्यान देने योग्य है कि ये दोनों लक्ष्य वैश्विक स्तर पर इस सदी के अंत तक के लिए, लंबे विचार-विमर्श और खींचतान के बाद, 2015 में पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते में निर्धारित किए गए थे।

विजय गर्ग

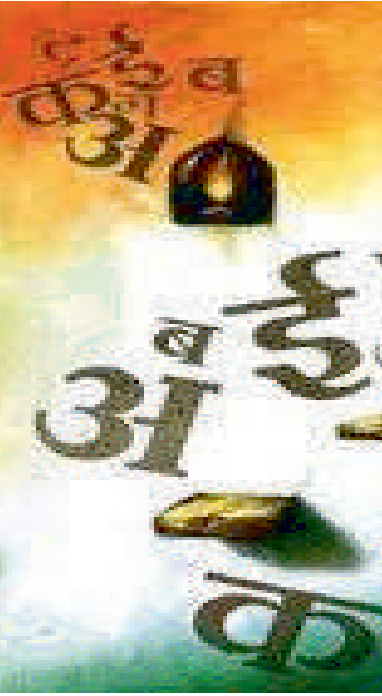
भाषा केवल संचार के माध्यम से कहीं अधिक है। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो धारणाओं को आकार देता है,

कारंवाई को प्रभावित करता है और समावेशिता-या बहिष्करण को बढ़ावा देता है। विकास क्षेत्र में, जहां परिवर्तन और प्रगति अक्सर संचार पर निर्भर करती है, भाषा की भूमिका और भी अधिक स्पष्ट हो जाती है। जब सही शब्दों का उपयोग किया जाता है, तो हाशिए पर रहने वाले समुदाय देखा, सुना और सम्मानित महसूस करते हैं। जब हानिकारक या बहिष्करणकारी भाषा बनी रहती है, तो यह विकास को अवरुद्ध कर सकती है और समानता लाने के प्रयासों में बाधा उत्पन्न कर सकती है। इसलिए, जिस तरह से संगठन भाषा का उपयोग करते हैं उसका लैंगिक असमानता को दूर करने की उनकी क्षमता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। भारत जैसे देश में, जहां लिंग जाति, वर्ग और धर्म जैसे कई कारकों से जुड़ा हुआ है, भाषा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। लिंग-समावेशी भाषा अब केवल 'अच्छी बात' नहीं रह गई है। यह एक आवश्यक, परिवर्तनकारी शक्ति है। लैंगिक सहयोग में भाषा की भूमिका लिंग-समावेशी भाषा का उपयोग करना लिंग सहयोगीता का एक रूप है जो संकेतिक इशारों से आगे बढ़कर सार्विक कारंवाई की ओर बढ़ती है। इस प्रकार की मित्रता खेल में शक्ति की गतिशीलता को गहरी समझ को दर्शाती है और सक्रिय रूप से मौजूदा संरचनाओं को नष्ट करने का प्रयास करती है। लैंगिक सहयोग न केवल महिलाओं या गैर-बाइनरी व्यक्तियों का समर्थन करने के बारे में है, बल्कि हम सभी के सोचने और बातचीत करने के तरीके को नया आकार देने के बारे में भी है। भाषा उस संज्ञानात्मक बदलाव को बनाने में मदद करती है। लिंग-आधारित भाषा हानिकारक शक्ति गतिशीलता को कायम रख सकती है। अपशब्द, ऐसी भाषा का एक दुर्भावनापूर्ण उपसहू, लंबे समय से व्यक्तियों को उनके लिंग या यौन पहचान के आधार पर अपमानित करने, चुप करने और कमतर करने के लिए उपयोग किया जाता है, और लोगों के आत्म-मूल्य और गरिमा पर स्थायी प्रभाव छोड़ सकते हैं। वे समावेशन में बाधाएं हैं, पूर्वाग्रहों को सुदृढ़ करते हैं और प्रणालीगत उत्पीड़न को कायम रखते हैं। इस प्रकार की भाषा एक हथियार के रूप में कार्य करती है, जो व्यक्तियों की अवसरों तक पहुंच को सीमित करती है और उन्हें समाज के हाशिये पर धकेल देती है। लिंग-तटस्थ भाषा हर किसी को देखा और सम्मानित महसूस करने की अनुमति देती है। उदाहरण के लिए, सर्वनाम परिचय का सामान्यीकरण या लिंग-तटस्थ सर्वनाम जैसे 'वे/वे' का उपयोग केवल राजनीतिक शुद्धता का कार्य नहीं है; यह एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देने के बारे में है जहां हर कोई आराम से रह सके। कई सेंटेंस में, बातचीत या मीडिया की शुरुआत में सर्वनाम का परिचय देने से लिंग-विविध व्यक्तियों को संकेत मिल सकता है कि वे एक सुरक्षित स्थान पर हैं। यह अधिक विश्वास और सहयोग की संभावनाएं खोलता है। जबकि लिंग-विविध समुदायों को इस परिवर्तन का नेतृत्व करना चाहिए, सहयोगियों के पास इन परिवर्तनों को बढ़ा देने मानने पर प्रभावशाली बनाने की शक्ति है विकास क्षेत्र हाशिए पर मौजूद समुदायों के साथ सीधे संपर्क करता है, इसलिए इसे सामाजिक परिवर्तन में सकसे आगे रहना चाहिए। इस दिशा में पहला कदम यह हो सकता है कि कार्यक्रमों को ऐसे तरीके से तैयार और संप्रेषित किया जाए जो सभी लिंगों के सम्मानजनक और समावेशी हो। विकास गैर-लाभकारी संस्था ACDI/VOCA की 2020 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, जो भाषा लैंगिक पहचान के विविध स्पेक्ट्रम को स्वीकार करने में विफल रहती है, वह कमजोर आबादी को हाशिये पर धकेल देती है और

परिवर्तन की भाषा

विकास कार्यक्रमों की प्रभावशीलता में बाधा डालती है। संवाद बॉक्स लिंग समावेशी भाषा के साथ महिलाओं का एक कोलाज सार्वजनिक संचार में समावेशी भाषा का सावधानीपूर्वक उपयोग समय के साथ सामाजिक दृष्टिकोण को बदलता है। भाषा हमारे सोचने और कार्य करने के तरीके को कैसे बदल देती है भाषा केवल वास्तविकता को वर्णन नहीं करती बल्कि उसे आकार देती है। हम जिन शब्दों का उपयोग करते हैं वे हमारे सोचने के तरीके और हमारे आसपास की दुनिया को समझने के तरीके को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, जिन भाषाओं में लिंगवाचक संज्ञा और सर्वनाम होते हैं, जैसे अंग्रेजी, वे अक्सर अधिक प्रतिबिंबित करती हैं पुरुषों और महिलाओं के लिए कठोर सामाजिक भूमिकाएं। दूसरी ओर, लिंग-तटस्थ सर्वनाम वाली भाषाएं - जैसे हिंदी ('आप'), कन्नड़ ('अवारु'), या तमिल ('अवारकल') - लिंग भूमिकाओं पर अधिक तरल और न्यायसंगत विचारों को प्रोत्साहित करती हैं। इसका विस्तार इस बात पर है कि विकास कार्यक्रम कैसे तैयार किये जाते हैं। जब नीतियों में लिंग-विशिष्ट भाषा का उपयोग किया जाता है, तो यह अनजाने में गैर-द्विआधारी व्यक्तियों को बाहर कर सकता है या पारंपरिक लिंग मानदंडों को सुदृढ़ कर सकता है। विचार करें कि गैर-बाइनरी लोगों को शामिल किए बिना कितनी बार सार्वजनिक कार्यक्रमों का विषयन 'माताओं', 'पिताओं', 'बेटों' और 'बेटियों' के लिए किया जाता है। विकास परियोजनाओं और पहलों के निर्माण में लिंग-समावेशी भाषा को शामिल करके इसे संबंधित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, विद्यार्थ साक्षरता प्रशिक्षण के लिए 'गृहिणियों' को लक्षित करने के बजाय, कार्यक्रम को 'देखभाल करने वालों' के समर्थन के रूप में तैयार करने से उन पुरुषों और गैर-बाइनरी व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा जो देखभाल करने वाले कर्तव्यों का पालन भी करते हैं। शब्दों में यह छोटा बदलाव यह सुनिश्चित करता है कि पहल अधिक समावेशी है और उन लोगों के व्यापक दायरे तक पहुंचती है जिन्हें समर्थन की आवश्यकता है। जैसा कि अक्सफैम ने अपने समावेशी भाषा गाइड में बताया है, सार्वजनिक संचार में समावेशी भाषा का सावधानीपूर्वक उपयोग समय के साथ सामाजिक दृष्टिकोण को बदल देता है। जो छोटे, सूक्ष्म परिवर्तन प्रतीत हो सकते हैं वे व्यापक सामाजिक स्वीकृति और परिवर्तन का कारण बन सकते हैं।

के लोगों को उन स्थानों पर नेविगेट करने के लिए मजबूर करता है जो उनके लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं। यह मुद्दा स्वास्थ्य सेवा से परे शिक्षा, रोजगार और कानूनी प्रणालियों तक फैला हुआ है - इन सभी तक पहुंच समाज में समृद्धि के लिए आवश्यक है। भारत जैसे देश में, जहां हिजड़ा समुदाय और अन्य लिंग-विविध समूहों को ऐतिहासिक रूप से कलंक का सामना करना पड़ा है, भेदभावपूर्ण भाषा पूरी आबादी को हाशिए पर डाल देती है और एक ऐसा वातावरण बनाती है जहां लोगों को उनके मूल अधिकारों से केवल इसलिए वंचित कर दिया जाता है क्योंकि वे पारंपरिक लिंग श्रेणियों में फिट नहीं होते हैं। लिंग-समावेशी भाषा में सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने की शक्ति होती है लिंग-समावेशी भाषा परिवर्तन का एक शक्तिशाली एजेंट है। अध्ययनों से पता चला है कि जो देश और संस्कृतियों लिंग-समावेशी भाषा को प्राथमिकता देते हैं, वे लैंगिक समानता के प्रति अधिक प्रगतिशील सामाजिक दृष्टिकोण प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया सरकार ने अपनी वेबसाइट पर लिंग-समावेशी भाषा के उपयोग की समीक्षा करने के लिए एक प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (एनएलपी) दृष्टिकोण लागू किया। एक अध्ययन में पाया गया कि जैसे-जैसे राज्य में लिंग-समावेशी शब्द अधिक आम होते गए, सार्वजनिक धारणा लिंग-विविध व्यक्तियों की अधिक स्वीकार्यता की ओर स्थानांतरित हो गई। समावेशी भाषा दृष्टिकोण को नया आकार दे सकता है। जबकि कई भारतीय भाषाओं में लिंग-तटस्थ सर्वनाम हैं, चुनौती स्थापित सामाजिक मानदंडों को बदलने में है। उसिनशैक्षिक अभियानों या सरकारी कार्यक्रमों में तटस्थ भाषा को शामिल करने वालों के समर्थन के रूप में तैयार करने से उन पुरुषों और गैर-बाइनरी व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा जो देखभाल करने वाले कर्तव्यों का पालन भी करते हैं। शब्दों में यह छोटा बदलाव यह सुनिश्चित करता है कि पहल अधिक समावेशी है और उन लोगों के व्यापक दायरे तक पहुंचती है जिन्हें समर्थन की आवश्यकता है। जैसा कि अक्सफैम ने अपने समावेशी भाषा गाइड में बताया है, सार्वजनिक संचार में समावेशी भाषा का सावधानीपूर्वक उपयोग समय के साथ सामाजिक दृष्टिकोण को बदल देता है। जो छोटे, सूक्ष्म परिवर्तन प्रतीत हो सकते हैं वे व्यापक सामाजिक स्वीकृति और परिवर्तन का कारण बन सकते हैं।



समावेशी भाषा को शामिल किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए लिंग-समावेशी शैली मार्गदर्शिकाएँ विकसित की जानी चाहिए कि सभी संचार लिंग विविधता की समझ को प्रतिबिंबित करें। इसके अतिरिक्त, क्षेत्र अनुसंधान, सर्वेक्षण और कार्यक्रम डिजाइन में विविध लिंग पहचान को समाजोचित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, सर्वेक्षण में उत्तरदाताओं को पुरुष और महिला श्रेणियों तक सीमित रखने के बजाय लिंग विकल्पों की एक श्रृंखला शामिल हो सकती है। बाह्य रूप से: हाशिये पर पड़े समुदायों के साथ सीधे काम करने वाले गैर-लाभकारी संगठनों के पास सार्वजनिक संचार में समावेशी भाषा का उपयोग करने का अवसर और जिम्मेदारी दोनों हैं। इस इतना सरल हो सकता है जितना यह सुनिश्चित करना कि सभी आउटरीच सामग्री तटस्थ शब्दों का उपयोग करती है जो द्विआधारी लिंग भूमिकाओं को सुदृढ़ नहीं करती हैं। उदाहरण के लिए, बाल कल्याण अभियानों में 'माँ' के स्थान पर 'माता-पिता' या 'पिता' के स्थान पर 'अभिभावक' को शामिल करना उन्हें अधिक समावेशी बना सकता है। संगठनों को अपने दृश्य संचार में विविध लिंग प्रतिनिधित्व को उजागर करने का भी लक्ष्य रखना चाहिए। जब छवियां, केस अध्ययन, या प्रशंसापत्र लगातार लैंगिक भूमिकाओं के बारे में एक संकीर्ण दृष्टिकोण दर्शाते हैं (उदाहरण के लिए, गुलाबी रंग में महिलाएं या सांकेतिक व्यक्ति के रूप में पुरुष), तो यह हानिकारक रूढ़िवादिता को मजबूत करता है। इसके बजाय, दृश्य कहानी कहने में विभिन्न प्रकार के चेहरे और लिंग की विशेषता समावेशी संचार का एक शक्तिशाली संदेश भेज सकता है। अनिताबी.ओआरजी का वार्षिक प्रेस हॉपर सैलिव्रेज (जीएचसी), महिला जैवोद्योगिकीविदों का दुनिया का सबसे बड़ा प्रतियोगिता, सक्रिय रूप से विविध लिंग प्रतिनिधित्व का उपयोग करता है। जीएचसी में, हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारा दृश्य संचार लिंग पहचान और भूमिकाओं के व्यापक स्पेक्ट्रम को प्रतिबिंबित करता है। केवल सिंजैडर महिलाओं को चित्रित करने के बजाय, यह कार्यक्रम नेतृत्व और नवाचार सहित विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में विविध व्यक्तियों-महिलाओं, ट्रांस व्यक्तियों, गैर-बाइनरी लोगों और सहयोगियों को प्रदर्शित करता

है। लिंग-समावेशी भाषा को लागू करने में चुनौतियाँ भारत में लिंग-समावेशी भाषा को अपनाना देखा की विशाल भाषाई विविधता के कारण विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण है। जबकि कुछ भारतीय भाषाएं ऑफर करती हैं लिंग-तटस्थ सर्वनाम, जैसे हिंदी में 'आप' (आप), वे अभी भी लिंगवाचक संज्ञाओं और क्रियाओं से परे हटते हैं जो पारंपरिक भूमिकाओं को मजबूत करते हैं। उदाहरण के लिए, हिंदी में, व्यवसायों के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्द, जैसे 'शिक्षक' (पुरुष शिक्षक) और 'शिक्षिका' (महिला शिक्षक), लिंग द्विआधारी को दर्शाते हैं। लिंग के आधार पर क्रियाएं भी बदलती हैं, उदाहरण के लिए, 'वो गई' (वह गई) और 'वो गया' (वह गया)। इससे लिंग पर जोर दिए जाने लोगों या भूमिकाओं पर चर्चा करना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह, तमिल में, हालांकि 'अवारका' (वे) जैसे सर्वनाम मौजूद हैं, लिंग भेद 'आसिरियार' (पुरुष शिक्षक) और 'आसिरिया' (महिला शिक्षक) जैसे शब्दों में अंतर्निहित है। यह जटिलता गुजराती और मराठी जैसी भाषाओं में बढ़ जाती है, जहां क्रिया और संज्ञा अक्सर लिंग के आधार पर बदल जाती हैं, जिससे समावेशी समकक्ष ढूंढना मुश्किल हो जाता है। भारत भर में आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं और अनगिनत बोलियों में लैंगिक समावेशिता की अवधारणाओं का अनुवाद करना और भी जटिल हो जाता है। एक भाषा की बारीकियाँ हमेशा दूसरी भाषा में नहीं चलती हैं, जिससे समावेशन प्रयासों में अंतराल पैदा होता है। इसके अलावा, कई गैर-लाभकारी संस्थाओं में नेतृत्व की भूमिकाएं पुरुष-प्रधान होती हैं, जिससे लिंग-तटस्थ भाषा पर जोर देना एक कठिन लड़ाई बन जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां साक्षरता दर अक्सर कम होती है और मौखिक संचार को प्राथमिकता दी जाती है, केवल लैंगिक-समावेशी भाषा पर लिखित सामग्री वितरित करना पर्याप्त नहीं हो सकता है। इसके बजाय, सामुदायिक कार्यशालाएँ, इंटरैक्टिव कहानी प्रचलन और भूमिका निभाने वाली गतिविधियाँ अंतर को घटाने में मदद कर सकती हैं। ये विधियाँ सुविधाकर्ताओं को समुदायों के साथ सीधे जुड़ने की अनुमति देती हैं, एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देती हैं जहां वास्तविक समय में लिंग मानदंडों पर सवाल उठाया जा सकता है और चर्चा की जा

सकती है। उदाहरण के लिए, गाँव की बैठकें यह प्रदर्शित करने के लिए भूमिका निभा सकती हैं कि भाषा कैसे धारणाओं को प्रभावित करती है, समुदाय के सदस्यों को यह समझने में मदद करती है कि लिंग-विशिष्ट शब्दों जैसे 'शिक्षक' या 'शिक्षिका' के बजाय 'शिक्षक' जैसे समावेशी शब्दों का उपयोग करना क्यों महत्वपूर्ण है। एक अभियान जो भाषा को 'महिला उद्यमी' (महिला उद्यमी) से बदलकर केवल 'उद्यमी' (उद्यमी) कर देता है, यह संदेश देता है कि किसी भी कल्पन होने की क्षमता में लिंग एक निर्णायक कारक नहीं है। कथा आकार देने वालों के रूप में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका पत्रकारों, संपादकों और मीडिया आउटलेट्स के पास या तो हानिकारक रूढ़िवादिता को मजबूत करने या अपनी भाषा विकल्पों के माध्यम से समावेशिता को बढ़ावा देने की शक्ति है। जब मीडिया-गतिमा, सम्मान और सटीकता के साथ विविध व्यक्तियों को रिपोर्ट करता है, तो यह न केवल सार्वजनिक धारणा को बदलता है बल्कि इन समुदायों को बहुत जरूरी दृश्यता भी प्रदान करता है। हम नियमित रूप से समाचार रिपोर्टों को गैर-द्विआधारी व्यक्तियों की यात्रा के प्रति असंवेदनशील होते हुए देखते हैं, जिसमें उनका नामकरण किया जाता है, मलत्त शब्दों का उपयोग किया जाता है, या संज्ञा के रूप में 'ट्रांसजेंडर' शब्द का उपयोग किया जाता है। यही कारण है कि मीडिया के लिए लिंग संवेदीकरण एक पूरक कारंवाई नहीं है बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए एक अभिन कदम है कि हम जो कहानियाँ सुनाते हैं वे उत्थानकारी हैं और जिसमें सभी को शामिल किया गया है। उदाहरण के लिए, इंडियन एक्सप्रेस की समाचार रिपोर्ट में मणिपुर प्रेश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जहां पूरी तरह से ट्रांसजेंडर टूरटालाना नहीं है, जिसमें टीम में ट्रांसमेन, ट्रांसवुमेन और अन्य समलैंगिक व्यक्तियों सहित अलग-अलग लिंग पहचान निर्दिष्ट की गई हैं। इस प्रकार रिपोर्टिंग न्यायसंगत और समावेशी तरीके से की गई। अनिताबी.ओआरजी इंडिया में, हम मीडिया के प्रभाव को पहचानते हैं और हमने लैंगिक संवेदनशीलता को अपनी पहुंच का केंद्रबिंदु बनाया है। पत्रकारों के लिए कार्यशालाओं के माध्यम से, हमारा लक्ष्य उन्हें लिंग-विविध समुदायों का सटीक प्रतिनिधित्व करना और हानिकारक को चुनौती देने के लिए उपकरणों से लैस करना है। चुनौतियों के बावजूद, आगे बढ़ेलिंग-समावेशी भाषा कहीं न कहीं से शुरू होनी चाहिए। छोटे कदम दृष्टिकोण बदलने और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। लगातार समावेशी भाषा का उपयोग करके, विकास संगठन अन्य क्षेत्रों के अनुसरण के लिए एक शक्तिशाली उदाहरण स्थापित कर सकते हैं। गैर-लाभकारी संस्थाएँ लैंगिक समावेशिता और भाषा पर केंद्रित कार्यशालाओं और प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन या उनमें भाग ले सकती हैं। इसके अतिरिक्त, मीडिया हाउस और संचार टीमों में लैंगिक समर्थन में विविध लिंग प्रतिनिधित्व को शामिल करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर सकते हैं। वास्तव में समावेशी भाषा की दिशा में अनुकूलन की आवश्यकता है। जैसे-जैसे हम अपने बढ़ते हैं, लिंग-विविध समुदायों से प्रतिक्रिया के लिए खुला रहना आवश्यक है, यह सुनिश्चित करते हुए कि समावेशिता के हमारे प्रयास वास्तव में उनकी आवश्यकताओं और अनुभवों को प्रतिबिंबित करते हैं। इस संवाद को विकसित करके और अपने दृष्टिकोण को लगातार परिष्कृत करके, हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जहां भाषा एक बाधा के बजाय एक पुल के रूप में कार्य करेगी।

ट्रैफिक पुलिस रात में घूम-घूम कर मीड को नियंत्रित कर रिपोर्ट देगी

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओइशा

भुवनेश्वर : द्वैतनगरी में गलियों की संख्या काफी बढ़ गयी है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, भुवनेश्वर और कटक की विभिन्न सड़कों पर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक दो शिफ्टों में ट्रैफिक पुलिस तैनात की जाती है। रात 10 बजे हाईवे पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी नजर नहीं आते। नतीजा यह होता है कि अगर किसी कारणवश रात 10 बजे के बाद भीड़ लग जाती है तो उसे नियंत्रित करने वाला कोई नहीं होता, इससे सड़क जाम हो जाती है और दुर्घटनाएं भी होती हैं। हालांकि ट्रैफिक पुलिस की ओर से इस पर रोक लगाने के साथ-साथ रात 10:00 बजे के बाद आवागमन को और भी आसान बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। राजधानी में रात 10 बजे के बाद भी ट्रैफिक पुलिस को सतर्क रखने का फैसला किया गया है। ट्रैफिक डीसीपी तापस दास ने भुवनेश्वर और कटक के ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों को पत्र लिखा है। जानकारी के मुताबिक, कुछ दिन पहले दोपहर करीब 12:00 बजे एक स्कोर्पियो गाड़ी ने स्वर्ण प्रीमियम स्ट्रीट के पास मेट्रो प्रोजेक्ट के बैरिकेड को टक्कर मार दी थी। हादसे के बाद चालक लेन

छोड़कर भाग गया। जैसे ही वाहन सड़क पर था और सड़क अचानक भीड़ हो गई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ट्रैफिक पुलिस को तैनात करना पड़ा। आधी रात में क्रेन बुलाकर सड़क हटवाने के बाद स्थिति सामान्य हुई। ईए एक घटना नहीं है, रात में कई दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिससे सड़क पर जाम लग जाता है। हालांकि, भविष्य में ऐसी समस्याओं से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा नए उपाय किए गए हैं। ट्रैफिक डीसीपी श्री दास ने भुवनेश्वर ट्रैफिक 1, 2, एनएच ट्रैफिक पुलिस स्टेशन और कटक ट्रैफिक पुलिस स्टेशन को पत्र लिखा है। प्रत्येक थाने से चार पुलिसकर्मीयों को दो बाइक पर अपने-अपने थाना क्षेत्र में गश्त करने को कहा गया है। वीएचएफ अपने पास रखने का आदेश दिया। टीम को रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक अपने थाना क्षेत्र में लौटने को कहा गया है। यदि किसी स्थान पर भीड़ दिखे तो तुरंत वहां पहुंचकर भीड़ को नियंत्रित करने को कहा गया है। किसी भी घटना या परेशानी की स्थिति में वीएचएफ को स्टेशन और कंट्रोल रूम को सूचना देने का निर्देश दिया गया है।



शिक्षा हर बच्चे का मूल अधिकार है. इसी को लेकर भारत के जाने माने अखिल भारतीय मानव कल्याण ट्रस्ट ने उठाया है कदम: डॉ हृदयेश कुमार

परिवहन विशेष न्यूज

अखिल भारतीय मानव कल्याण ट्रस्ट के संस्थापक डॉ हृदयेश कुमार ने प्रौ शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई तरह से लोगों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं इस ट्रस्ट की स्थापना 2018 में हुई थी तभी से प्रौ शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा दे रहे हैं सेंक्टर 2 फरीदाबाद और सेंक्टर 56 फरीदाबाद और अन्य कई जगहों पर प्रौ शिक्षा प्रदान कर रहे हैं डॉ हृदयेश कुमार का कहना है कि अपने और अपने परिवार के लिए तो सभी जीते हैं लेकिन यही जीवन अगर किसी और के लिए जीते हैं तो उस जिन्दगी की खुशी सौ गुनी हो जाती है वैसे तो सरकार द्वारा भी बहुत सारे कार्य किया जा रहा है

पूरे प्रदेश सहित देश के स्कूलों में एडमीशन की प्रक्रिया चल रही है. जगह-जगह स्कूलों के होर्डिंग्स और पोस्टर्स लगे हुए हैं. हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें. वह होर्डिंग्स और पोस्टर्स को देखकर और अपने जान पहचान वालों से स्कूलों के बारे में जानकारी भी ले रहे हैं. अमीर लोग तो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, लेकिन दिक्कत है मिडिल और गरीब तबके के परिवार वालों को. दरअसल आजकल सरकारी स्कूलों में पढ़ाई ठीक से होती है लेकिन लोगों का नजरिया बदला हुआ है, वहीं प्राइवेट स्कूलों की फीस ज्यादा है. ऐसे में मां बाप चिंता में हैं कि वह कम फीस में अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाए कैसे. ऐसे पेरेंट्स की चिंता दूर करने के लिए केंद्र सरकार



राइट टु एजुकेशन (RTE) योजना लेकर आई है. जिसके तहत मिडिल क्लास फैमिली भी अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिला सकती है. क्या है RTE योजना भारत सरकार 2005 में RTE (शिक्षा का अधिकार) योजना एक्ट लाई थी. इस कानून के मुताबिक देश के हर बच्चे को शिक्षा लेने का फंडामेंटल राइट है. भारत सरकार ने 6 से 14 साल की उम्र के हर बच्चे को प्रौ और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया है. सरकार भारत सरकार ने 4 अगस्त 2009 को इस एक्ट को बनाया और 1 अप्रैल, 2010 को इसे लागू किया गया. इस योजना के तहत प्राइवेट स्कूल में 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित रखनी होती हैं, ताकि प्रत्येक बच्चे

को मुफ्त शिक्षा प्राप्त हो सके प्रौ शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए 248 बच्चों समेत अखिल भारतीय मानव कल्याण ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जा रहा है इन सभी को कॉपी किताब पेन पेंसिल ड्रेस आदि सभी सुविधा ट्रस्ट द्वारा दी जाती है ट्रस्ट को 12A और 80G और MSME, CSR व नीति आयोग द्वारा प्रमाणित किया गया है और ISO द्वारा मान्यता प्राप्त है आप भी इस सहयोग में अपनी सेवा करना चाहते हैं तो ट्रस्ट के बैंक खाता नंबर 153302000000160 IFSC CODE UTKS0001533 Name AKHIL BHARTIYA MANAV KALYAN TRUST या फोन पेव Paytm Number 8920446101

नवीन पटनायक की 2 अभिनव पहल 'मो बस' और 'मो ई-राइड' सेवाओं को केंद्र में सम्मानित किया



मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओइशा

भुवनेश्वर : नवीन की 2 अभिनव पहल 'मो बस' और 'मो ई-राइड' सेवाओं को केंद्र में सम्मानित किया गया है। केंद्र सरकार ने परिवहन विभाग में ओडिशा को देश के सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया है। जानकारी के मुताबिक, भुवनेश्वर को देश में सबसे अच्छे सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहर के रूप में मान्यता दी गई है। भुवनेश्वर को 'सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहर' के रूप में मान्यता दी गई है और राजधानी में चलने वाली 'मो बस' और 'मो ई-राइड' प्रणालियों के लिए पुरस्कार दिया गया है। ओडिशा की इन 2 प्रमुख परियोजनाओं ने केंद्रीय आवास और

शहरी मामलों के मंत्रालय से यह पुरस्कार जीता है। गुजरात के गांधीनगर में आयोजित 17वें अर्बन मॉबिलिटी इंडिया (यूएमआई) कार्यक्रम में ओडिशा को यह पुरस्कार दिया गया। कार्यक्रम में आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री ने भाग लिया और राज्य सरकार की ओर से सम्मान स्वीकार किया। परिवहन के मामले में भुवनेश्वर ने देश के बड़े शहरों को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल किया है। सरकार की यह सुविधा शहर के नागरिकों के विशेष लाभ के लिए सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करने में कामयाब रही है। कुत ताराप की MoBus और MoE-राइड सेवाओं को देश में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के रूप में मान्यता दी गई

है। पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की 2 बड़ी योजनाओं 'माई बस' और 'माई ई-राइड' की अब पूरे देश में तारीफ हो रही है। इसके साथ ही नवीन पटनायक के पद छोड़ने के बाद भी देश की जनता उनकी जमकर तारीफ कर रही है। 'मो बस सेवा की शुरुआत 2018 में ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने की थी। बाद में भुवनेश्वर में मो ई-राइड सेवा भी शुरू की गई। यह सिस्टम राजधानी भुवनेश्वर और कटक के साथ पुरी, ब्रह्मपुर, राउरकेला और संबलपुर जिलों में जारी है। आम लोगों के लिए परिवहन की लागत कम करने की सरकार की यह पहल लोगों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

लेखनी को पलने और बढ़ने का माहौल देता उत्तराखंड का 'लेखक गांव'

'लेखक गांव' लेखकों, कवियों, साहित्यकारों और अन्य रचनाकर्मीयों द्वारा महसूस की जा रही व्यावहारिक कठिनाइयों का निवारण करने की ओर एक अभिनव पहल है। उत्तराखंड में यह पहला लेखक गाँव भविष्य का पर्यटक गंतव्य बनकर उभरेगा। यह मंच उन लेखकों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो अपने शब्दों के माध्यम से समाज को नयी राह दिखाने का सामर्थ्य रखते हैं। लेखक गाँव के वातावरण में सृजनशीलता का प्रवाह अनेक लेखकों और कवियों को प्रेरित करेगा।

-डॉ सत्यवान सौरभ

देहरादून के निकट सुरम्य हिमालयी क्षेत्र में स्थित थानो गाँव ने देश के अपनी तरह के पहले 'लेखक गाँव' का गौरव हासिल किया है। इस गाँव की अविधारणा से लेकर उसका विकास उत्तराखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया है जो स्वयं एक विशिष्ट साहित्यकार के रूप में भी पहचान रखते हैं। उनका दावा है कि इस गाँव में लेखकों को अपनी कृतियों के सर्जन के लिए जरूरी एक शांत और रचनाशील वातावरण मिलेगा। देश के पहले लेखक गाँव थानो में स्पृश हिमालय फाउंडेशन द्वारा हाल ही में आयोजित रमेश हिमालय महोत्सव-2024र भारतीय साहित्य, संस्कृति और कला की समृद्ध धरोहर का प्रतीक बन गया। इस ऐतिहासिक आयोजन में उत्तराखण्ड के पहले रलेखक गाँव का उद्घाटन हुआ, जहाँ लेखक और विचारक प्रकृति के सान्निध्य में सृजनात्मक चिंतन की स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। हिमालयीय वैशिष्ट्यता लिए 'लेखक गाँव' का उद्देश्य देश-दुनियाँ के उन विलक्षण, विद्वान साहित्यकारों, गीतकारों, कलाकारों को तैर प्रदान करना है, जिनकी लेखनी नेअपने समय की कालजयी रचनाओं का सर्जन कर आमजन के बीच लोकप्रियता हासिल की। रलेखक गाँव का यह अनूठा आयोजन न केवल साहित्यकारों को प्रेरणा प्रदान करेगा, बल्कि इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यहाँ लेखक कुटीर, संजीवनी वाटिका, नक्षत्र और नगप्रह वाटिका, पुस्तकालय और गंगा व हिमालय संग्रहालय जैसी संरचनाओं ने इसे एक सम्पूर्ण साहित्यिक तीर्थ बना दिया है।

25 से 27 अक्टूबर 2024 को स्पृश हिमालय फाउंडेशन के तत्वावधान में देहरादून के थानो में स्थित लेखक गाँव में अंतरराष्ट्रीय कला, साहित्य और संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया।



इस पाँच दिवसीय महोत्सव में 65 से अधिक देशों के साहित्यकार, लेखक और कलाकारों ने भाग लिया, जो हिन्दी भाषा और उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने में कामयाब हुए। यह महोत्सव हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार का एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ और इसमें भाग लेने वाले विदेशी साहित्यकार अपने देशों में हिन्दी के ब्रांड एंबेसडर के रूप में कार्य करेंगे। देवभूमि उत्तराखण्ड का यह रलेखक गाँव प्रदेश की अद्भुत रचनात्मकता और सृजनशीलता का प्रतीक है। यहाँ का शांत और सुरम्य वातावरण लेखकों को सर्जन के लिए एक आदर्श स्थान

प्रदान करता है। चिंतन, मनन और स्वयं की खोज में रलेखक गाँव जैसे स्थानों की महत्ता है। ऐसे एकांत और सृजनात्मक वातावरण में लेखकों को आत्म-साक्षात्कार का सजीव अनुभव प्राप्त होता है। लेखक गाँव की मूल परिकल्पना को यथार्थ के धरातल पर उतारते हुए 'लेखक कुटीर' इस परिसर का सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनाओं को सहेजता है। जीवन के तमाम कड़वे-मीठे अनुभवों और झंझावतों को स्वयं में समेटे ऐसे व्योमवृद्ध लेखकों के लिए यह परिसर स्वयं में स्नेह और आशोष की छाँव में स्थापित एक ऐसा स्थान है जहाँ प्रतिक्षण मानवता की सेवा चरितार्थ होगी। विश्व के हिमालयीय सरोकारों से जुड़े प्रसिद्ध



लेखकों, साहित्य साधकों एवं कालाकारों के नाम से 'लेखक कुटीर' नाम की तख्ती सजी होगी। प्रकृति के आँचल में नाना प्रकार के फूलों की सुगन्धित खुशबू पूरे परिसर को सकारात्मक ऊर्जायुक्त तरंगों से महका देगी। अध्ययन, लेखन और जीवन को जीवंत बनाने के लिए 'लेखक कुटीर' में निवास कर रहे लेखकों को यथासम्भव सुविधाएँ उपलब्ध कराने का प्रयास किया जायेगा। लेखक गाँव के ग्रंथालय में समस्त हिमालय राज्यों के साहित्य, संस्कृति, इतिहास, सामाजिक, राजनितिक, भूगोल, दर्शन, धर्म, ज्ञान-विज्ञान आदि विषयों से सम्बंधित ग्रंथों को स्थान दिया गया है और भी दिया जाएगा। प्राचीन ऐतिहासिक मूर्तियों, चित्रों, सिक्कों, पाण्डुलिपियों एवं अन्य दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह किया जाएगा। पहाड़ी चित्र कला, विश्व स्तरीय फोटोग्राफरों के चित्र ग्रंथालय की शोभा बढ़ाएंगे।

ग्रंथालय का अतिरिक्त परिवेश निर्मित करते हुए इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि परिव्रता और शांति का वातावरण बना रहे। ग्रंथालय का निर्माण हिमालयी लोक संस्कृति, वास्तु शिल्प के उद्घरण रूप में निर्मित होगा। पहाड़ी गाँव के भवन निर्माण शिल्प के आधार पर हिमालय ग्रंथालय का निर्माण किया जाएगा जिसमें खोली, छज्जा एवं तिवारी बनाई जाएगी। ग्रंथालय पहाड़ी पत्थर एवं स्थानीय ककशठ से निर्मित किया जाएगा। ग्रंथालय का निर्माण हिमालयी लोक संस्कृति, वास्तु शिल्प के उद्घरण रूप में निर्मित होगा। लेखक गाँव में अपने वाले छात्रों, शोधार्थियों, लेखकों एवं विभूतियों सहित सभी आगंतुकों की आवासीय व्यवस्था, भवन का परिवेश केवल छात्रावास या विश्रामगृह तक सीमित न हो कर सुख, परम शांति और अद्भुत आनन्द से परिपूर्ण घर का पूर्ण आभास प्रदान करेगा। आवासीय

परिसर प्रकृति के मध्य आगंतुकों के चित और चिंतन को नव ऊर्जा प्रदान करके आवासीय समय को सकारात्मक, रचनात्मक तथा अविस्मरणीय बनायेगा। रलेखक गाँव जैसे स्थान भारत के साहित्य और संस्कृति को नई ऊँचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। इनमें होने वाले महोत्सव साहित्य, कला और संस्कृति के विविध रंगों को संरक्षित और सशक्त बनाते हुए भारत की सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध करने का संकल्प दोहराते हैं। लेखक गाँव के रमेश हिमालय महोत्सव-2024र ने साहित्यिक और सांस्कृतिक जागरूकता का नया अध्याय लिखा है। यह आयोजन न केवल उत्तराखण्ड की धरती पर रचनात्मकता का संचार लाया है बल्कि साहित्य, संस्कृति और कला के माध्यम से भारतीय धरोहर को संजोए रखने में सहायक सिद्ध होगा।